मनेन्द्रगढ़
28 मई 2026 गुरुवार

दैनिक
मीडियाऑडीटर

मनेन्द्रगढ़, रीवा एवं सतना से एक साथ प्रकाशित

ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में एफआईआर दर्ज

2025 में कोलकाता के ईद कार्यक्रम में सनातन को गंदा धर्म कहने का आरोप

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ममता पर आरोप है कि उन्होंने 2025 में कोलकाता में आयोजित ईद कार्यक्रम के दौरान सनातन और हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विवाद उस बयान को लेकर है, जिसमें 'गंदा धर्म' जैसे शब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, इस मामले पर ममता की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह शिकायत वकील रिंकी चटर्जी सिंह ने की है। उनका कहना है कि बयान से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। रिंकी ने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत में कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता पहले भी हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। रिंकी के मुताबिक उन्होंने 2025 में भी शिकायत करने की कोशिश की थी लेकिन तब उनकी नहीं सुनी गई और उन्हें प्रताड़ित भी किया गया था।

TMC नेता ने भी बयान को गलत बताया: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दार्जिलिंग यूनिट के महासचिव और वकील अत्री शर्मा ने भी इस बयान को गलत बताया है। उनका कहना है कि पार्टी के अंदर भी कई लोग इस टिप्पणी से सहमत नहीं थे और किसी को भी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है।

गुजरात-दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू

इसमें पूरे गोवा और इंदौर जैसे शहरों को 24 घंटे बिजली देने की क्षमता

भुज, एजेंसी। भारत ने ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन (हरित ऊर्जा परिवर्तन) में इतिहास रच दिया है। अडाणी समूह की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कच्छ सीमा पर स्थित खवड़ा में कुल 3.37 गीगावाट/घंटे की क्षमता का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) शुरू कर दिया है।

चीन को छोड़कर पूरी दुनिया में एक ही जगह पर बना यह सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट है। यहां रखी बैटरियों में सौर या पवन ऊर्जा से बनी बिजली को स्टोर कर जरूरत पड़ने पर किसी भी शहर को सप्लाई दी जा सकती है। रिकॉर्ड 10 महीने में बने इस सिस्टम से पूरे गोवा, इंदौर-चंडीगढ़ जैसे शहरों या यूं कहें कि 10 लाख घरों को 24 घंटे बिजली दी जा सकती है। यह स्टोरेज 1.2 करोड़ एलईडी बल्ब 10 घंटे लगातार जलाकर रख सकता है।

भारत ने जम्मू-कश्मीर पर चीन-पाकिस्तान का बयान खारिज किया

कहा- दूसरे देश को टिप्पणी का हक नहीं; चीन ने इतिहास से जुड़ा विवाद बताया था

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर के जिक्र को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। भारत ने चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) परियोजनाओं पर भी कड़ी आपत्ति जताई। यह बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चीन यात्रा के बाद जारी संयुक्त बयान के जवाब में आया है। इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने चीन को जम्मू-कश्मीर के हालात की जानकारी दी। इसके बाद चीन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर मुद्दा इतिहास से जुड़ा विवाद है और इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर, UNSC प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए।

भारत ने चीन के CPEC का विरोध भी किया: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि CPEC के कुछ प्रोजेक्ट भारत के उस क्षेत्र से गुजरते हैं, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध और जबरन कब्जा कर रखा है। भारत किसी भी ऐसी कोशिश का विरोध करता है, जो पाकिस्तान के कब्जे को मजबूत या वैधता देने की कोशिश करे।

बांके बिहारी मंदिर के पास विकास योजना तैयार करे यूपी सरकार, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के आसपास एक व्यापक विकास योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस योजना में सड़कों को चौड़ा करने के साथ-साथ बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और बीमार श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ ने परंपराओं और आधुनिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाने के लिए यह अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर के आसपास व्यावसायिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए। साथ ही होटलों, धर्मशालाओं, पीने के पानी, शौचालय, आपातकालीन निकास और सार्वजनिक परिवहन की बेहतर व्यवस्था हो। बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। कोर्ट ने वृंदावन की तंग गलियों पर चिंता जताते हुए कहा कि तिरुपति की तरह यहां जगह ज्यादा नहीं है, इसलिए प्रशासन को सुरक्षा के लिए कुछ अलग हटकर सोचना होगा।

सुनवाई के दौरान पुजारियों (सेवायतों) की ओर से दलील दी गई कि मंदिर के देवता एक 'जीवित बालक' के समान हैं। उनके जागने, पूजा करने और दोपहर में विश्राम करने का एक निश्चित समय सदियों से चला आ रहा है। इसे प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं बदला जाना चाहिए। पुजारियों ने दर्शन के समय में बदलाव, पारंपरिक 'देहरी पूजा' को रोकने और 'फूल बंगला सेवा' के लिए 1.51 लाख रुपये की भारी फीस वसूलने पर भी आपत्ति जताई।

प्रशासन और गोस्वामी समुदाय के बीच बातचीत की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई-पावर्ड कमेटी (HPC) में चार पुजारी प्रतिनिधियों को शामिल करने का आदेश दिया। इनमें रजत गोस्वामी, शैलेंद्र गोस्वामी, गोपेश गोस्वामी और हिमांशु गोस्वामी शामिल हैं। ये प्रतिनिधि धार्मिक परंपराओं और मंदिर के समय को लेकर कमेटी को सुझाव देंगे। न्यायमूर्ति बागची ने जोर देकर कहा कि परंपराएं चलती रहनी चाहिए, लेकिन श्रद्धालुओं का शोषण बंद होना चाहिए।

यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश 2025 से जुड़ा है। इस कानून के जरिए सरकार मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में लेना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस कानून के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी थी और मंदिर के कामकाज की देखरेख के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी बनाई थी।

प्री-मानसून बारिश 29 मई से 5 जून तक संभव:

90% भारत कवर करेगी, केरल में नमी कमजोर इसलिए अटका मानसून; यूपी के बांदा में तापमान 47.4डिग्री

नई दिल्ली/ भोपाल/ जयपुर/ लखनऊ, एजेंसी। भारत के 80-90% हिस्से में 29 मई से 5 जून तक प्री-मानसून बारिश हो सकती है। यह बारिश इसलिए अहम है क्योंकि मानसून अभी केरल नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग ने 26 मई का अनुमान लगाया था।

मानसून आने के लिए केरल के 14 तय स्टेशनों में लगातार दो दिन 2.5 एमएम बारिश जरूरी है। दक्षिण-मध्य अरब सागर में चक्रवाती सर्कुलेशन से बादल कमजोर हुए हैं। अगले 2-3 दिन में मानसून आगे बढ़ सकता है।

यूरोपीय मौसम एजेंसी यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्ट्स (ECMWF) ने भारत में 15 दिनों की बारिश का पूर्वानुमान निकाला है। ECMWF सैटेलाइट, समुद्री और वायुमंडलीय डेटा के आधार पर मौसम का मैप बनाता है। इसकी तस्वीर में अगले 8 दिनों में दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और बंगाल की खाड़ी से लगे इलाकों में ज्यादा बारिश के संकेत नजर आ रहे हैं। मई के आखिरी सप्ताह में सूर्य की किरणें भारत के बड़े हिस्से पर लगभग सीधी पड़ती हैं। इससे जमीन तेजी से गर्म होती है और तापमान बढ़ जाता है।

यूपी का बांदा में 47.4 डिग्री पारा, एक बार फिर देश में सबसे गर्म.... फिलहाल उत्तर-पश्चिम, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत में गर्मी का असर ज्यादा है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश का बांदा एक बार फिर देश में सबसे गर्म शहर रहा। यहां अधिकतम तापमान 47.4डिग्री दर्ज किया गया। यह लगातार नवां दिन था जब यहां तापमान 47 डिग्री के पार पहुंचा। बांदा के अलावा उत्तर प्रदेश के पांच और जिलों में तापमान 45डिग्री से ज्यादा रहा, इनमें उरई 45.8डिग्री, झांसी 45.5डिग्री, आगरा 45.3एष्ट और हमीरपुर 45.2डिग्री शामिल हैं।

गुजरात के कच्छ से 1180 करोड़ की कोकीन जत

ब्राजील से आई खेप दिल्ली भेजने की तैयारी थी; तीन विदेशी गिरतार, एक

कच्छ (गुजरात),एजेंसी। गुजरात में कच्छ से करीब 1180 करोड़ रुपए कीमत की 118 किलो कोकीन जब्त की गई है। इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट किए गए तीनों ही आरोपी विदेशी हैं। गुजरात DGP डॉ. केएलएन राव ने बताया कि सूचना मिलने के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस मुंद्रा पोर्ट पर एक संयुक्त ऑपरेशन चला रही थीं। इसी के तहत मंगलवार की सुबह भारतीय समुद्री सीमा से एक कंटेनर जहाज पकड़ा गया। जहाज ब्राजील, कई लैटिन अमेरिकी देशों, मेक्सिको, अमेरिका और कराची होते हुए गुजरात के तट तक पहुंचा था। जहाज में नाइजीरिया की नागरिकता वाले दो आरोपी सवार थे, जिनमें से एक समुद्र में कूदकर फरार हो गया। पकड़े गए एक आरोपी ने बताया कि खेप दिल्ली के द्वारका में रहने वाले दो लोगों तक पहुंचाई जाने वाली थी।

इनकी पहचान क्लैविन चुकवुमा (तंजानिया का नागरिक) और ब्यारुहांगा जेम्स (युगांडा का नागरिक) के रूप में हुई है। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि कोकीन की डिलीवरी देश में किसे और कहां होने वाली थी।

जहाज से समुद्र में फेंके जा रहे थे पैकेट गुजरात एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक यह जहाज मुंद्रा तट से करीब 5 नॉटिकल मील (करीब साढ़े 9 किमी) दूर लंगर डाले खड़ा था। कोस्टगार्ड ने की घंटों तक इस पर नजर रखी। इसी दौरान अधिकारियों ने देखा कि जहाज से कुछ संदिग्ध बैग समुद्र में फेंके जा रहे हैं। इसके बाद कोस्टगार्ड और ATS की संयुक्त टीम हरकत में आई और रात में ही जहाज को घेरकर अपने कब्जे में ले लिया। जो आरोपी पकड़ाया, वो नाइजीरिया का रहने वाला एटीएस की छापेमारी में जहाज पर दो लोग मिले थे। इनमें से जुम्मा नासिर उमर नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यह मूल रूप से नाइजीरिया का रहने वाला है। वहीं, एक अन्य आरोपी ने समुद्र में छलांग लगा ली थी, जिसकी तलाश की जा रही है। जहाज को कच्छ पोर्ट पर लाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट बोला :

एसआईआर अवैध नहीं, चुनाव आयोग ने कानून के मुताबिक काम किया

वह लिस्ट से हटाए संदिग्ध नाम 4 हफ्ते में केंद्र को भेजे

पटना, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार समेत पांच राज्यों में हुए चुनाव के दौरान की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग को SIR के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है और यह मनमाना नहीं है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को संदिग्ध नागरिकता के आधार पर वोटर लिस्ट से हटाए गए व्यक्तियों के नाम चार हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश भी दिया है। चुनाव आयोग ने 11 महीने पहले विधानसभा चुनाव वाले बिहार से SIR की शुरुआत की थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में SIR कराया गया। असम में स्पेशल रिवीजन (SR) हुआ था।

पटियाला में नीले ड्रम में युवती की लाश मिली बॉडी पैक कर लाल रंग का ढक्कन लगा चेहरे पर खरोंच, हाथ पर नेहा लिखा

पटियाला,एजेंसी। पटियाला में मंगलवार को नीले रंग के ड्रम में एक युवती की लाश मिली। यह ड्रम रेलवे कॉलोनी में पड़ा हुआ था। हत्यारों ने शव को ड्रम के अंदर ठूंसा और ऊपर लाल रंग का ढक्कन लगा दिया, ताकि किसी को शक न हो। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। युवती के एक हाथ पर 'नेहा' लिखा हुआ है, जबकि दूसरे हाथ पर दिल का टैटू बना है। इस टैटू के अंदर अंग्रेजी के अक्षर 'ह' और '' गुदे हुए हैं। युवती के चेहरे पर खरोंच के निशान भी हैं। शव को कब्जे में लेकर राजिंदरा अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस युवती की पहचान कराने की कोशिश कर रही है। पुलिस को शक है कि प्रेम संबंधों के चलते युवती का कत्ल कर ड्रम में पैक कर फेंका गया है। कत्ल भी दूसरी जगह किया गया और लाश को ड्रम में पैक करने के बाद कार में डालकर यहां फेंका गया है।

नीट मामला- CBI ने दो और अरेस्ट किए, कुल 13 गिरफ्तार

इनमें एक डॉक्टर, बेटे समेत 3 छात्रों को पेपर दिलवाया; एक कोचिंग टीचर भी पकड़ाया

नई दिल्ली, एजेंसी। नीट पेपर लीक मामले में CBI ने बुधवार को दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहले आरोपी की पहचान डॉक्टर मनोज शिरूरे के रूप में हुई है। वह लातूर के रहने वाले हैं। डॉ. मनोज ने एक कोचिंग सेंटर के मालिक (जो खुद भी आरोपी है) के बेटे समेत तीन छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर दिलाए थे। वहीं पकड़ा गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षदकुमार शाह है। वह पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी (APMA) में फिजिक्स पढ़ाता है। उसे NEET परीक्षा के लीक हुए फिजिक्स के क्वेश्चन गिरफ्तार आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। इस मामले में पूरी कड़ी और साजिश का पता लगाने के लिए जांच जारी है। CBI ने अब तक अलग-अलग जगहों पर 49 स्थानों पर तलाशी ली और कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

खुलासा- नीट का पेपर 5 राज्यों में बिका: सीबीआई जांच में खुलासा हुआ कि नीट का पेपर 5 राज्यों में बिका था। सबसे ज्यादा बिक्री महाराष्ट्र में हुई। दूसरा नंबर राजस्थान का है। सीबीआई का कहना है कि बाद पेपर लीक का मामला और बड़ा निकल सकता है। एजेंसी अभी यह तय नहीं कर पा रही कि कितने छात्रों ने पेपर खरीदा था।

हाईकोर्ट का फैसला: आसाराम को करना होगा सरेंडर, सजा बरकरार

नाबालिग से यौन उत्पीड़न केस में 2 आरोपी बरी, करीब एक महीने बाद सुनाया डिसीजन

जोधपुर, एजेंसी। राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर) ने बुधवार (27 मई) सुबह आसाराम की सजा पर फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के केस में आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है।

जस्टिस अरूण मोंगा व जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। केस में सह आरोपी शिल्पी व शरतचंद को बरी किया गया है। आसाराम फिलहाल अंतरिम जमानत पर है, लेकिन उसे अब सरेंडर करना होगा।

अगस्त 2013 में जोधपुर स्थित आश्रम में एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप केस के आरोप में आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। लंबी सुनवाई के बाद जोधपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को उन्हें दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

प्यासे को पानी जरूर पिलाएं, भारत के कई हिस्सों में लू के प्रकोप के बीच पीएम मोदी की लोगों से अपील

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नागरिकों से देश भर में बढ़ते तापमान के प्रति सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे खुद को हाइड्रेटेड रखें, बाहर निकलते समय अपने साथ पानी रखें और जरूरतमंदों की मदद करें। कई राज्य अभी भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे मौसम की इन चरम स्थितियों के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

'जितना हो सके उतनी सावधानियां बरतें': उन्होंने लिखा, 'देश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी में गर्मी के कारण होने वाली कई मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। मैं अपने सभी साथी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे जितना हो सके, उतनी सावधानियां बरतें।

'प्यासे को पानी जरूर पिलाएं'... प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, 'कृपया खुद को हाइड्रेटेड रखें और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बनती है। यदि संभव हो तो किसी भी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी जरूर पिलाएं।

पीएम मोदी ने इन लोगों की सराहना... उन्होंने उन लोगों की भी सराहना की, जो राहगीरों के लिए अपने घरों और दुकानों के बाहर पीने का पानी रखते हैं। उन्होंने आगे लिखा, 'मैं उन लोगों की भी सराहना करता हूं जो अपने घरों और दुकानों के बाहर घड़ों में पानी रखते हैं, ताकि कोई भी उससे पानी पी सके।

मौसम की दोहरी मार: यूपी-बिहार में आंधी-बारिश बनी आफत, कई राज्यों में लू का प्रकोप; 16 लोगों की मौत

लखनऊ, पटना, एजेंसी। बिहार और उत्तर प्रदेश में आंधी-बारिश के चलते हुए हादसों में करीब 16 लोगों की मौत हो गई। तेज हवाओं, बिजली आपूर्ति ठप होने, पेड़ और पोल गिरने तथा फसलों के नुकसान से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बिहार के भागलपुर और आसपास के जिलों में सोमवार रात 110 किलोमीटर प्रतिघंटे तक की रफ्तार से चली हवा और वर्षा ने व्यापक तबाही मचाई। इससे हुए हादसों में आठ लोगों की मौत हो गई। भागलपुर में 200 से अधिक स्थानों पर पेड़ गिर गए और 300 से अधिक बिजली पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे 23 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। कई इलाकों में पानी का संकट गहरा गया। केला, आम और लीची की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा।

तेज आंधी से अस्पताल की खिड़कियों के शीशे टूटे: जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एचडीयू वार्ड की खिड़कियों के शीशे टूट गए और मरीजों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट करना पड़ा। वार्ड में पानी भर गया, जिससे मरीजों, तीमारदारों, डॉक्टर व स्टाफ सहित अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मधेपुरा, दरभंगा और मधुबनी में भी तेज आंधी से मकान, स्कूल भवन और पेड़ क्षतिग्रस्त हुए। मौसम विभाग ने दक्षिण बिहार में बादल छाए रहने और सीमांचल क्षेत्र में आंधी-पानी की प्रबल संभावना जताई है।

उत्तर प्रदेश में भी आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई: उत्तर प्रदेश में भी आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई है। लखीमपुर, गोंडा, सीतापुर, बस्ती और संतकबीरनगर समेत विभिन्न जिलों में आठ लोगों की मौत हो गई। कई जगह टिनशेड उड़ गए। मकानों की दीवारें और स्कूलों की बाउंड्रीवाल गिर गई। लखीमपुर के कारीबडेरी गांव में आंधी के दौरान लगी आग में 40 घर जल गए। बिजली पोल टूटने से कई गांव अंधेरे में डूब गए। गोंडा में रेल ट्रैक पर पेड़ गिरने से ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ और वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रास्ते में खड़ी रहीं। दूसरी ओर प्रदेश के 30 जिलों में बुधवार को भी लू चलने की चेतावनी जारी की गई है।

छत्तीसगढ़ में यलो अलर्ट जारी: छत्तीसगढ़ के दक्षिण और मध्य जिलों में मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। यहां 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है। राजनांदगांव 46.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य में सबसे गर्म रहा।

उत्तराखंड में हीट वेव का यलो अलर्ट जारी: उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी रही, जिसके चलते हीट वेव का यलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि, पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा और ओलावृष्टि से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने 29 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने मैदानी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को चंबा में हल्की वर्षा हुई, जबकि अन्य क्षेत्रों में तेज धूप रही। ऊना में तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने 28 से 30 मई के बीच वर्षा, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जताई है।

मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं: जम्मू समेत मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से फिलहाल राहत के आसार नहीं हैं। कठुआ 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य में सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग के अनुसार मई के अंत तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि, 28 और 29 मई को कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और हल्की वर्षा की संभावना है।

पंजाब में पारा 46 के पास: पंजाब में बठिंडा 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य में सबसे गर्म रहा। लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में भी लू चली। मौसम विभाग ने 28 और 29 मई को 60 से 70 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी, हल्की वर्षा और ओलावृष्टि का आरेंज अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ भी भीषण गर्मी की चपेट में है। अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राजस्थान में पारा 45 के पार: मौसम विभाग ने हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 28 मई के बाद तेज हवाओं और वर्षा से राहत मिलने की संभावना जताई है। राजस्थान में मंगलवार को गर्मी का प्रकोप जारी रहा।

वह अब हिमालय का हिस्सा, एवरेस्ट पर ही रहेगा हैदराबाद के पर्वतारोही का शव; परिवार का फैसला

हैदराबाद, एजेंसी। हैदराबाद के 53 वर्षीय पर्वतारोही और टेक प्रोफेशनल अरुण कुमार तिवारी के परिवार ने फैसला किया है कि उनका शव माउंट एवरेस्ट पर ही रहने दिया जाएगा। अरुण तिवारी की पिछले हफ्ते एवरेस्ट से उतरते समय हिलेरी स्टेप के पास मौत हो गई थी। परिवार ने कहा कि यह फैसला सिर्फ पैसों की वजह से नहीं लिया गया, बल्कि उनकी धार्मिक आस्था, हिमालय के प्रति अरुण तिवारी के प्रेम और शव को वापस लाने की बेहद कठिन प्रक्रिया को देखते हुए लिया गया है। जिस जगह उनकी मौत हुई, उसे 'डेथ जोन' कहा जाता है, जहां से शव लाना बेहद जोखिम भरा माना जाता है। भारतीय टीम का संचालन करने वाली पायनियर एडवेंचर ने पहले शव को 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई से नीचे लाने के लिए 1.14 लाख डॉलर यानी करीब 1.1 करोड़ रुपये का खर्च बताया था। बाद में इसे घटाकर 94 हजार डॉलर यानी करीब 89.7 लाख रुपये किया गया। कंपनी के मालिक निवेश कार्की ने कहा कि शव लाना एवरेस्ट फतह करने से भी ज्यादा खतरनाक काम होता है। निवेश कार्की के अनुसार, कैंप-4 से अंतिम चढ़ाई शुरू करने के बाद अरुण तिवारी बेहद थक गए थे। उनके निजी शेरपा गाइड ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कार्की ने बताया कि अरुण तिवारी ने कहा था कि जब शिखर इतना करीब और साफ दिखाई दे रहा है, तब वह अपना सपना अधूरा नहीं छोड़ सकते। उन्होंने आखिरकार एवरेस्ट फतह कर लिया, लेकिन नीचे उतरते समय हिलेरी स्टेप के पास उन्हें खून की उल्टी होने लगी। शेरपाओं ने अतिरिक्त ऑक्सीजन देकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अरुण तिवारी भारतीय अभियान दल का हिस्सा थे, जिसमें 46 वर्षीय संदीप अरे भी शामिल थे। संदीप अरे की भी एवरेस्ट से उतरते समय मौत हुई थी, लेकिन उनका शव नीचे लाया जा सका क्योंकि उनकी मौत कम ऊंचाई पर हुई थी।

परिवार ने बताया धार्मिक कारण: अरुण तिवारी अपने पीछे पत्नी और दो बेटियों को छोड़ गए हैं। उन्होंने 2025 में भी एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से 7200 मीटर की ऊंचाई से वापस लौटना पड़ा था।

इस सीजन में उन्होंने दोबारा प्रयास किया। अरुण तिवारी के साले सुधीर उपाध्याय ने कहा कि परिवार ने धार्मिक मान्यताओं और हिमालय के आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए शव को वापस न लाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, 'हमारे धार्मिक ग्रंथों में हिमालय को माता पार्वती का पिता माना गया है। वहां मृत्यु होने पर व्यक्ति वैकुंठधाम जाता है। उन्हें वापस धरती पर लाना पाप माना जाता है।' सुधीर उपाध्याय ने कहा कि परिवार अरुण तिवारी की मौत को 'समाधि' की तरह देखता है। उन्होंने कहा, 'वह अब हिमालय का हिस्सा बन चुके हैं, एक तरह से भगवान शिव का हिस्सा।'

फरीदाबाद में एसआईआर बीएलओ 15 जून से घर-घर सत्यापन करेंगे

फरीदाबाद, एजेंसी। जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य विशेष अभियान के लिए पहली जुलाई अर्हता तिथि निर्धारित की है।

पांच जून से 14 जून तक मतदाता सूची की तैयारी, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा जरूरी दस्तावेज की छपाई का कार्य किया जाएगा। इसके बाद 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। साथ ही 14 जुलाई तक मतदान केंद्रों का युक्तिकरण (रैशनलाइजेशन) भी पूरा कर लिया जाएगा। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 21 जुलाई को किया जाएगा। इसके बाद 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्राप्त दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 21 जुलाई से 18 सितंबर तक चलेगी। इसके पश्चात 22 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

पाक की मध्यस्थता पर सवाल: ट्रंप के करीबी सीनेटर ने कहा- इस्राइल से दुश्मनी का भाव रखता है, ईरान की मदद भी

वाशिंगटन डीसी,एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित सीजफायर वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की निष्पक्षता पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस्राइल के प्रति पाकिस्तान की पुरानी दुश्मनी उसे मध्यस्थ की भूमिका के लिए समस्याग्रस्त बनाती है।

ग्रहाम ने कौन सा मुद्दा उठाया: ग्रहाम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरानी सैन्य विमानों को पाकिस्तान के एयरबेस पर जगह दी जा रही है। उन्होंने पाकिस्तान के वरिष्ठ नेताओं के इस्राइल विरोधी बयानों को भी बेहद परेशान करने वाला बताया।

पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बोले: उन्होंने लिखा कि काफी समय से मुझे लगता रहा है कि पाकिस्तान का मध्यस्थ बनना बेहद समस्याग्रस्त है। इस्राइल के प्रति उनकी दुश्मनी पुरानी है। यह भी साफ है कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तान के एयरबेस पर मौजूद हैं और पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं के बयान बेहद चिंताजनक हैं।

पाकिस्तान ने ठुकराया अमेरिका का अब्राहम समझौता: यह बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें पाकिस्तान से अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने को कहा गया था। पाकिस्तानी चैनल समा टीवी को दिए इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे किसी समझौते में शामिल होना चाहिए जो हमारी मूल विचारधारा से टकराता हो।

पाकिस्तान ने इस्राइल पर जताया अविश्वास: उन्होंने इस्राइल पर अविश्वास जताते हुए कहा कि आप उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनकी बात पर एक दिन के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता? आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का इस मुद्दे पर रुख हमेशा साफ रहा है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की पासपोर्ट नीति का भी जिक्र किया और कहा कि हम शायद दुनिया का इकलौता देश हैं जिसके पासपोर्ट में इस्राइस का नाम तक नहीं होता।

हमास के सैन्य विंग प्रमुख को इस्राइल ने किया ढेर सात अक्तूबर के नरसंहार का था मास्टरमाइंड

तेल अवीव, एजेंसी। इस्राइली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने गाजा में हमास के सैन्य विंग के नए प्रमुख मुहम्मद ओदेह को मार गिराया है। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। इस्राइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी पुष्टि की। मुहम्मद ओदेह सात अक्तूबर को हुए नरसंहार के दौरान हमास के खुफिया विभाग का प्रमुख था। उसे हमास के नौसैनिक कमांडर के रूप में भी जाना जाता था और उसने कई आतंकवादी हमलों की योजना बनाई थी। ओदेह को लगभग एक सप्ताह पहले ही नियुक्त किया गया था, ताकि वह दो हफ्ते पहले आईडीएफ के हमले में मारे गए इज्जेदीन अल-हद्दाद की जगह ले सके। ओदेह इस्राइली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों की हत्या और अपहरण के लिए भी जिम्मेदार था।

सात अक्तूबर नरसंहार में शामिल सभी लोगों को करेंगे खत्म : नेतन्याहू: प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए हमास के सैन्य विंग के नए प्रमुख मुहम्मद ओदेह को मार गिराए जाने की पुष्टि की। इसके साथ ही उन्होंने सात अक्तूबर 2023 के नरसंहार में शामिल सभी लोगों को खत्म करने का संकल्प दोहराया।

भरोसे के लायक नहीं अमेरिका हमलों पर भड़का ईरान इंटरनेट बहाली के बीच फिर बढ़ा तनाव

तेहरान, एजेंसी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हमलों के बाद तेहरान ने अमेरिका पर युद्धविराम तोड़ने और बदनीयती दिखाने का आरोप लगाया है। ईरान ने साफ कहा है कि वह किसी भी हमले का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ लंबे समय से बंद इंटरनेट सेवाओं को भी अब धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है। इस बीच होर्मुज जलडमरूमध्य, तेल सप्लाई और युद्धविराम वार्ता को लेकर पूरी दुनिया की नजरें खाड़ी क्षेत्र पर टिक गई हैं। अमेरिकी सेना ने सोमवार को दक्षिणी ईरान में कुछ ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई रक्षात्मक थी और इसमें मिसाइल लॉन्च साइट्स तथा बारूदी सुरंग बिछाने वाली नौकाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने दावा किया कि उसने संयम के साथ कार्रवाई की।

लेकिन ईरान ने इसे सीधा युद्धविराम का उल्लंघन बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है और अब हर परिणाम की जिम्मेदारी वॉशिंगटन की होगी। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने यह भी दावा किया कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे एक ड्रोन को मार गिराया और दूसरे ड्रोन तथा लड़ाकू विमान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।

क्या बातचीत और युद्धविराम अब खतरे में है: ईरान और अमेरिका के बीच कतर में बातचीत चल रही थी, जिसका मकसद युद्धविराम को आगे बढ़ाना और हालात को सामान्य करना था। लेकिन ताजा हमलों के बाद स्थिति फिर तनावपूर्ण हो गई है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची कतर से लौट चुके हैं। हालांकि आगे की रणनीति पर अभी कुछ साफ नहीं कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि युद्धविराम और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर खोलने पर बातचीत में अभी कुछ दिन लग सकते हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी साफ दिखाई दे रही है।

इंटरनेट बंद होने से ईरान को कितना नुकसान हुआ: ईरान ने कई महीनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद रखीं। सरकार का कहना था कि यह कदम युद्ध और सुरक्षा कारणों से उठाया गया। अब धीरे-धीरे इंटरनेट बहाल किया जा रहा है। कुछ इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवा शुरू हो गई है, लेकिन मोबाइल इंटरनेट अभी पूरी तरह चालू नहीं हुआ है। इंटरनेट बंद होने से विदेशों में रह रहे ईरानी अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। ऑनलाइन कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हुए। रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेट बंद रहने से ईरान की अर्थव्यवस्था को हर दिन 3 से 4 करोड़ डॉलर तक का नुकसान हुआ। पहले भी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट बंद किया गया था।

जासूसी के आरोप में फांसी और होर्मुज पर बढ़ी चिंता: ईरान ने इस्राइल के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को फांसी दे दी। ईरानी एजेंसी मिजान ऑनलाइन के मुताबिक, गुलामरेजा खानी शकराब पर मोसाद के लिए काम करने और लोगों की भर्ती करने का आरोप था।

मोदीनगर में सीकरी रोड पर जगह जगह मिले मांस के टुकड़े, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा

मोदीनगर, एजेंसी। गाजियाबाद के मोदीनगर में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीकरी रोड पर जगह-जगह मांस के टुकड़े मिलने की सूचना फैली। यह खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने इस मामले में हंगामा शुरू कर दिया है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि ईद से पहले असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस रास्ते पर मांस के टुकड़े मिलने की बात की जा रही है उसी रास्ते से होकर श्रद्धालु सीकरी माता मंदिर जाते हैं। सामाजिक सद्भाव को गंभीरता से लेते हुए पुलिस इस मामले में पूरी सतर्कतात बरतते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस मामले में हिंदू रक्षा दल की तरफ से थाने में शिकायत दी गई है।

पटौदी में 23 किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार और 4 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी, 8 करोड़ आएगी लागत

पटौदी, एजेंसी। पटौदी विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलने वाली है। पटौदी क्षेत्र की विधायक बिमला चौधरी ने क्षेत्र की जर्जर हो चुकी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों के पुनर्निर्माण की मंजूरी दिलवा दी है वहीं चार अन्य नई सड़कों के निर्माण की भी मंजूरी दिलवा दी है। विधायक बिमला चौधरी ने बताया कि मार्केटिंग बोर्ड की राजपुरा से लुहारी, जाटौली से शेरपुर वाया मंदपुरा, डाडावास से हालियाकी वाया शेरपुर, राजपुरा से कारोला, महचाना से फरीदपुर, महचाना से खंडेवला, राजपुरा से जोनावास वाया मऊ की लगभग 23 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने लगभग 5.78 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त महचाना श्मशान घाट से ढाणी महचाना और पचपीरा मंदिर पालड़ी से गांव की सीमा तक, जोनियावास से जाटोला तथा मंदपुरा से जटशाहपुर तक के कुल चार नए सड़क मार्गों के निर्माण के लिए 2.19 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि इन सड़कों के टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। शीघ्र ही ये सड़कें अस्तित्व में आएंगी। इससे हजारों ग्रामीणों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी।

केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के खिलाफ ईडी का एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10 ठिकानों पर रेड

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को CMRL मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास समेत कई जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार, राज्य में कुल 10 परिसरों पर तलाशी ली जा रही है। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की है। जांच एजेंसी ने तिरुवनंतपुरम स्थित पिनराई विजयन के किराए के घर पर भी छापा मारा। मामले में आरोप है कोचिन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने 2018 से 2019 के बीच पिनराई विजयन की बेटी टी वीना की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 1.72 करोड़ रुपये का अवैध भुगतान किया था। आरोप है कि आईटी कंपनी ने सीएमआरएल को कोई सेवा नहीं दी थी। मंगलवार को केरल हाई कोर्ट ने सीएमआरएल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कंपनी ने ईडी की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी। ईडी ने इन आरोपों की जांच के लिए साल 2024 में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था।

पाकिस्तान में फिर दबे हिंदू विरासत के निशान क्यों रुका सड़कों के पुराने नाम लौटाने का फैसला

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान में फिर दबे हिंदू विरासपाकिस्तान के लाहौर में सड़कों और गलियों के पुराने ऐतिहासिक नाम बहाल करने की योजना अब कट्टरपंथी दबाव की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले विभाजन से पहले के मूल नाम दोबारा बहाल करने की मंजूरी दी थी, लेकिन विरोध बढ़ने के बाद इस फैसले को फिलहाल रोक दिया गया है। अगर यह योजना लागू होती, तो लाहौर की कई सड़कें और इलाके फिर से अपने पुराने हिंदू और सिख नामों से पहचाने जाते। इस पूरे मामले ने पाकिस्तान में इतिहास, पहचान और कट्टरपंथ को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

आखिर क्या था मरियम सरकार का फैसला: लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल योजना के तहत शहर की पुरानी सांस्कृतिक पहचान वापस लाने की कोशिश की जा रही थी। इसी के तहत पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की संयुक्त बैठक में कई सड़कों और गलियों के पुराने नाम बहाल करने को मंजूरी दी गई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 20 मार्च को इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की थी। योजना का मकसद बंटवारे से पहले के लाहौर की ऐतिहासिक विरासत को दोबारा सामने लाना था। लेकिन फैसले के सार्वजनिक होते ही कट्टरपंथी संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया।

सरकार अचानक अपने फैसले से पीछे क्यों हट गई: विरोध बढ़ने के बाद पंजाब सरकार अब अपने पुराने रुख से पीछे हटती दिखाई दे रही है।

मझौली के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में विशेष शिक्षण समर कैंप का शुभारंभ

योग, खेल, रचनात्मक गतिविधियों और व्यक्तित्व विकास से जुड़ रहे छात्र-छात्राएं

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशानुसार विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं जीवन कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझौली में पांच दिवसीय विशेष शिक्षण समर कैंप का शुभारंभ 27 मई से किया गया। यह शिविर 31 मई 2026 तक संचालित होगा। ग्रीष्मावकाश के दौरान आयोजित इस समर कैंप में छात्र-छात्राओं के साथ अभिभावकों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की। शिविर का शुभारंभ विकासखंड शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र सिंह, विकासखंड समन्वयक अयोध्या प्रसाद पटेल, सीएम राइज प्राचार्य किशन लाल विश्वकर्मा, मॉडल प्राचार्य मती इंदिरा कचेर, बीएसी

कमलाकर सिंह, जन शिक्षक पदमधर द्विवेदी एवं संतोष कुमार वर्मा सहित शिक्षकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में हुआ समर कैंप में विद्यार्थियों को स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जोड़ते हुए योग, प्राणायाम, खेल गतिविधियां, रचनात्मक गतिविधियां और व्यक्तित्व विकास से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य छात्र-छात्राओं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, अनुशासन एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करना है इसके अंतर्गत ड्राइंग-पेंटिंग, लोकगीत, कविता वाचन, एक्सपोजर विजिट, स्वतंत्र लेखन, स्वतंत्र वाचन और विभिन्न खेल गतिविधियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जा रहा है साथ ही

स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं शिविर के प्रथम दिन स्वास्थ्य जीवनचर्या, योग एवं शारीरिक शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षित योग शिक्षक ज्ञानेंद्र तिवारी ने छात्र-छात्राओं को योग एवं व्यायाम का प्रशिक्षण दिया इस अवसर पर विजयपाल कोरी, राकेश गुप्ता, मनोज कुमार वर्मा, संदीप कुमार नामदेव, जग्गू यादव, राजेश्वर सिंह सहित अन्य कर्मचारी एवं अभिभावक उपस्थित रहे यह समर कैंप विद्यार्थियों के अवकाश को सीखने, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास के अवसर में बदलने की सार्थक पहल बन रहा है।

शासकीय हैंडपंप से हटाया गया अतिक्रमण, ग्रामीणों को फिर मिली पेयजल सुविधा

प्रशासन की कार्रवाई के बाद भैंसरहा गांव में आमजन के लिए बहाल हुआ हैंडपंप

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के तहसील रामपुर नैकिन अंतर्गत ग्राम भैंसरहा में शासकीय हैंडपंप पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाते हुए आम ग्रामीणों के लिए पेयजल सुविधा पुनः बहाल कर दी है। उपखंड अधिकारी रामपुर नैकिन विकास आनंद के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई से गांव के लोगों को बड़ी राहत मिली है जानकारी के अनुसार ग्राम भैंसरहा स्थित शासकीय हैंडपंप पर एक व्यक्ति द्वारा निजी उपयोग के लिए मोटर लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया था। आरोप है कि राजेंद्र मणि द्विवेदी द्वारा लगाए गए इस निजी मोटर कनेक्शन के कारण शासकीय पेयजल स्रोत का उपयोग आम नागरिकों के लिए बाधित हो रहा था। ग्रामीणों को पानी भरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और कई लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत की थी शिकायत प्राप्त होने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल

संज्ञान लिया। उपखंड अधिकारी विकास आनंद के निर्देश पर प्रशासनिक दल मौके पर पहुंचा और जांच के बाद हैंडपंप पर लगाए गए निजी मोटर को हटवाकर अतिक्रमण समाप्त कराया गया। कार्रवाई के बाद शासकीय हैंडपंप को दोबारा आमजन के उपयोग के लिए उपलब्ध करा दिया गया प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से गांव के लोगों में संतोष देखा गया। ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से शासकीय हैंडपंप का लाभ सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा था लेकिन अब अतिक्रमण हटने के बाद गांव के सभी नागरिक बिना किसी बाधा के पेयजल प्राप्त कर सकेंगे उपखंड अधिकारी विकास आनंद ने स्पष्ट कहा कि शासकीय संसाधनों पर किसी भी प्रकार का निजी कब्जा या दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधाओं में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने ग्रामीणों से भी अपील की है कि किसी भी शासकीय संपत्ति या सार्वजनिक सुविधा के दुरुपयोग की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें ताकि समय रहते उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

नगर पालिका सीधी में पेयजल समस्याओं के समाधान हेतु कंट्रोल रूम स्थापित

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए मुख्य सचिव के निर्देशों के पालन में नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मुख्य सचिव द्वारा 24 मई 2026 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की सतत निगरानी एवं समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे। इसी के अनुपालन में नगर पालिका परिषद सीधी के नवीन कार्यालय भवन के कक्ष क्रमांक-11 में कंट्रोल रूम प्रारंभ किया गया है कंट्रोल रूम के लिए शीलध्वज सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 9589181756 है। इनके सहयोग के लिए सुरेश प्रसाद पाण्डेय (8085695252), सौरभ शुक्ला (9977887004) एवं हर्षित तिवारी (8319836406) को तैनात किया गया है कंट्रोल रूम में पदस्थ कर्मचारी प्रतिदिन उपस्थित रहकर पेयजल से संबंधित शिकायतों का पंजीयन करेंगे। नागरिक दूषित पेयजल आपूर्ति, पाइपलाइन से जल आपूर्ति बाधित होना, पाइपलाइन लीकेज, हैंडपंप खराब होना जैसी समस्याओं की जानकारी कंट्रोल रूम में दे सकेंगे। प्राप्त शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक तत्काल पहुंचाकर 24 घंटे के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। नगर पालिका परिषद ने नागरिकों से अपील की है कि पेयजल संबंधी किसी भी समस्या की स्थिति में कंट्रोल रूम से संपर्क कर सुविधा का लाभ उठाएं।

कटे-फटे होंठ एवं तालु से पीड़ित बच्चों के लिए स्क्रीनिंग शिविर आयोजित, 6 बच्चे सर्जरी हेतु जबलपुर रेफर

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिला चिकित्सालय सीधी स्थित डीईआईसी (क्म्प्ब) भवन में बुधवार को कटे-फटे होंठ एवं तालु से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दुबे सर्जिकल हॉस्पिटल जबलपुर के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं प्रदान कर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया यह शिविर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में आयोजित किया गया। शिविर का निरीक्षण अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धनंजय मिश्रा ने किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया शिविर में कुल 10 बच्चों का पंजीयन किया गया, जिनमें से 6

बच्चों को सर्जरी के लिए उपयुक्त पाया गया। इन बच्चों को विशेष वाहन के माध्यम से उपचार एवं सर्जरी हेतु जबलपुर रेफर किया गया शिविर में डॉ. स्वाति सिंह डेंटल सर्जन, पुष्पेंद्र शुक्ला डीईआईसी प्रबंधक, सावित्री मिश्रा नर्सिंग ऑफिसर सहित समस्त स्टाफ ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया इसी अवसर पर डीईआईसी भवन में विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस तथा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम के तहत तंबाकू निषेध संबंधी गतिविधियां संचालित की गईं तथा छात्राओं के बीच रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धनंजय मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके सानिध्य में पूरे कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया कॉलेज की छात्राओं ने सहभागिता कर माहवारी स्वच्छता एवं तंबाकू निषेध के संदेश को प्रभावी ढंग से प्रसारित किया इस अवसर पर आरकेएसके के परामर्शदाता, मास्टर ट्रेनर्स, पीआरसी स्टाफ सामाजिक न्याय विभाग के कर्मचारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित, 40 प्रतिशत अनुदान का लाभ मिलेगा

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत मछुआरों और मत्स्य पालन से जुड़े हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के तहत सीधी जिले में ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन, मत्स्य उत्पादन झींगा पालन एवं प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत सभी वर्गों के पात्र हितग्राहियों को इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान गतिविधि पूर्ण होने के बाद डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे हितग्राही के बैंक खाते में जमा किया जाएगा योजना का लाभ लेने के इच्छुक ग्रामीण तालाबों के 10 वर्षीय पट्टाधारक हितग्राही मछुआ समूह स्व-सहायता समूह एवं मछुआ सहकारी समितियां निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 जून 2026 निर्धारित की गई है आवेदन मत्स्य विभाग के जिला कार्यालय वीथिका परिसर, कलेक्ट्रेट के सामने सीधी में जमा किए जा सकते हैं योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक सहायक संचालक मत्स्योद्योग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं अथवा मोबाइल नंबर 8889026748 एवं 7692001789 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मत्स्य पालन से आय बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने का यह बेहतर अवसर है, पात्र हितग्राही समय सीमा के भीतर आवेदन करना सुनिश्चित करें।

सोन नदी से अवैध रेत उत्खनन पर 4 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, वन विभाग-पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा सोन घड़ियाल अभयारण्य में कार्रवाई

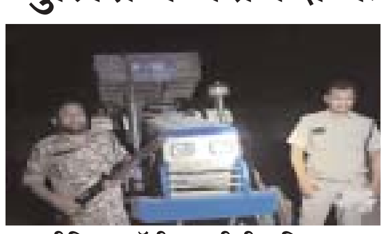

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सीधी जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है मंगलवार की देर रात सोन नदी के भेलकी घाट पर घेराबंदी कर चार ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गईं यह क्षेत्र सोन घड़ियाल अभयारण्य के अंतर्गत आता है जहां लंबे समय से चोरी-छिपे अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा था संजय टाइगर रिजर्व परिक्षेत्र सहायक सिहावल संजीव कुमार सोनकर के नेतृत्व में गठित एक विशेष टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया टीम ने मौके से अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहे चार ट्रैक्टर मय ट्रॉली को पकड़ा इसके बाद सभी जब्त वाहनों को सुरक्षार्थ जमोड़ी पुलिस थाना में खड़ा कराया गया।

शिकायत के बाद वन विभाग ने की कार्रवाई: वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 27, 29, 39ष्ठ एवं 51 तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा 2, 41 एवं 52 के तहत वन अपराध पंजीबद्ध किया है। अधिकारियों ने बताया कि सोन घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध उत्खनन से प्राकृतिक पर्यावरण और वन्यजीवों को गंभीर नुकसान पहुंच रहा था जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थीं।

अवैध उत्खनन पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी: इस पूरी कार्रवाई में वनरक्षक रमेश कुमार सोनकर, सुरेश चंद्र तिवारी, सर्वेश कुमार मिश्रा, शेर बहादुर पटेल एवं सुरक्षा श्रमिक जगदीश सोनकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं, जब्त वाहनों को सुरक्षित थाना जमोड़ी तक पहुंचाने में परिक्षेत्र सहायक कठौतहा कमलापति त्रिपाठी, वनरक्षक संजय कुमार सिंह, वेद शुक्ला, विनीत शर्मा, सुरक्षा श्रमिक विनय सिंह, दीपेंद्र सिंह, देवराज सिंह तथा जमोड़ी पुलिस ने अहम सहयोग किया वनरक्षक संजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि ये ट्रैक्टर कई दिनों से रात के अंधेरे में चोरी-छिपे रेत का उत्खनन और परिवहन कर रहे थे। लगातार निगरानी और सूचना तंत्र सक्रिय करने के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर सभी वाहनों को पकड़ने में सफलता हासिल की। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स को दी प्राथमिकताओं की स्पष्ट रूपरेखा

जनहित के कार्यों में तेजी लाएं, शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करें : मुख्य सचिव

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी कलेक्टर्स को सुशासन, जनकल्याण और समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर हों और सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कोई भी शिकायत 50 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहनी चाहिए मुख्य सचिव ने नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरण तय समय सीमा में निराकृत कराने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध

नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही मानसून को देखते हुए बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियां पहले से पूरी रखने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जन-धन की हानि को न्यूनतम रखा जा सके उन्होंने सड़क सुरक्षा को गंभीर विषय बताते हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने, ब्लैक स्पॉट कम करने, हेलमेट अनिवार्यता लागू कराने और सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी ई-डार पोर्टल पर तत्काल दर्ज कराने के निर्देश दिए। दुर्घटना पीड़ितों को प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत निरूशुल्क उपचार उपलब्ध कराने और राहवीर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया मुख्य सचिव ने अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि दोषियों पर लगाए गए जुर्माने की प्रभावी वसूली भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खेती की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए कलेक्टर्स खेती, पशुपालन, मछलीपालन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी गतिविधियों की नियमित समीक्षा करें। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देकर स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया उन्होंने बताया कि सभी जिलों में ई-विकास सिस्टम लागू हो चुका है, इसलिए अब खाद का वितरण केवल ई-टोकन के माध्यम से किया जाए।

स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर फूटा जनाक्रोश सरई सीएचसी की अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन

नगर परिषद अध्यक्ष ने समर्थकों संग तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, तीन दिन में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले के सरई स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बुधवार को स्थानीय नागरिकों का आक्रोश खुलकर सामने आया। नगर परिषद सरई की अध्यक्ष अनुराधा सिंह मरकाम ने अपने समर्थकों एवं क्षेत्रीय नागरिकों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और तहसीलदार धर्म प्रकाश मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की ज्ञापन में सीएचसी सरई की स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा गया कि लंबे समय से अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है, जिससे क्षेत्र की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष अनुराधा सिंह मरकाम ने आरोप लगाया कि अस्पताल में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के कई पद रिक्त पड़े हुए हैं जिसके कारण मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपये की लागत से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट लंबे समय से बंद पड़ा है और आईसीयू सुविधा भी अब तक शुरू नहीं हो सकी है। गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार के लिए अन्य शहरों के अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है जिससे गरीब और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक एवं मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है ज्ञापन में यह भी बताया गया कि अस्पताल की एक्स-रे मशीन पिछले तीन वर्षों से खराब पड़ी हुई है इसके कारण मरीजों को निजी अस्पतालों में महंगी जांच कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके परिजनों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शव वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से शोकाकुल परिवारों की परेशानियां और बढ़ जाती हैं नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण सरई क्षेत्र के नागरिक मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की इस दौरान समाजसेवी प्रेम सिंह भाटी ने भी अस्पताल की समस्याओं को गंभीर बताते हुए प्रशासन से शीघ्र समाधान की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तीन दिनों के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं किया गया तो क्षेत्रीय नागरिकों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

ट्रॉली विवाद में दो पक्षों में लाठी-डंडों चले कई घायल, शुरू हुई कहासुनी मारपीट में बदली

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र के नौढिया कुल्हुई गांव में बुधवार दोपहर करीब 2 बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली के विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला किया इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है जानकारी के अनुसार, गांव निवासी वीरेंद्र पाल ने साहू परिवार से एक ट्रैक्टर-ट्रॉली किराए पर ली थी।

कुछ समय बाद, लकड़ी चोरी के एक मामले में वन विभाग ने ट्रॉली जब्त कर ली इसके बाद से साहू परिवार लगातार अपनी ट्रॉली या उसके एवज में पैसे की मांग कर रहा था बताया गया है कि इस विवाद के बाद वीरेंद्र पाल मजदूरी के लिए प्रदेश से बाहर चला गया था और दो दिन पहले ही गांव लौटा था बुधवार को साहू परिवार के सदस्य वीरेंद्र पाल के घर पहुंचे और ट्रॉली व पैसे की मांग करने लगे इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई इस मारपीट में एक पक्ष से वीरेंद्र पाल, उनकी पत्नी अंकिता पाल, बेटी रेनू पाल और प्रियंका पाल घायल हो गए साहू परिवार के भी तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं घटना की सूचना मिलते ही माड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया थाना प्रभारी ने बताया कि करीब एक माह पहले साहू परिवार ने ट्रैक्टर-ट्रॉली गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी जिस पर समझौता भी हुआ था बुधवार को यह विवाद फिर से ट्रॉली को लेकर हुआ है पुलिस ने प्राथमिक रूप से मामला दर्ज कर लिया है।

एनटीए के बाद सीबीएसई

संपादकीय

यह सीबीएसई अधिकारी ही बता सकते हैं कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन में गड़बड़ी के कारण क्या हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम का काम जिसे दिया गया, वह इसे करने में दक्ष नहीं था। त्रासदी यह है कि ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। मेडिकल कालेजों में प्रवेश की परीक्षा नीट के प्रश्नपत्र लीक हो जाने के कारण इस परीक्षा को निरस्त करने के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में जिस तरह विसंगतियों की शिकायतें सामने आ रही हैं, वे निराशाजनक भी हैं और दुर्भाग्यपूर्ण भी। इसी कारण शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ने जैसे नीट का आयोजन करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए एवं शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया था, वैसे ही सीबीएसई के चेयरमैन को भी अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है।

उनसे पूछा जाएगा कि सीबीएसई परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन में गड़बड़ियां क्यों सामने आ रही हैं? पता नहीं वे क्या जवाब देते हैं और उनसे संसदीय समिति संतुष्ट होती है या नहीं, लेकिन प्रश्न केवल उसके संतुष्ट होने का नहीं है। प्रश्न यह है कि सीबीएसई उन छात्रों को संतुष्ट कर पाएगा या नहीं, जो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन में गड़बड़ी की शिकायत कर रहे हैं? ध्यान रहे ऐसी कई शिकायतों को सीबीएसई ने सही पाया है। इसका अर्थ है कि सीबीएसई की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में वास्तव में कोई खामी है। यह कहना कठिन है कि कितने छात्र पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में खामी के शिकार हैं, लेकिन जब ऐसा होता है तो छात्रों और साथ ही अभिभावकों का परीक्षा मूल्यांकन की प्रक्रिया से भरोसा उठता है। इसी के साथ परीक्षा आयोजन करने वाली संस्था की साख पर भी बट्टा लगता है।

यह सामान्य बात नहीं कि जहां कुछ छात्र यह पा रहे हैं कि बोर्ड द्वारा अपलोड की गई उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कापी उनकी लिखावट से मेल नहीं खा रही है, वहीं कुछ की यह शिकायत है कि सही उत्तर के बाद भी उनके अंक काट दिए गए। कुछ यह भी कह रहे हैं कि स्कैन कापी देखकर समझना कठिन है कि उत्तर पुस्तिका किसकी है? यह ठीक है कि सीबीएसई अधिकारी विसंगतियों को ठीक कर रहे हैं और शिकायत करने वाले छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन इससे केवल समय और संसाधन की बर्बादी ही नहीं होगी, बल्कि अन्य छात्रों के मन में भी यह आशंका घर करेगी कि उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन सही तरह हुआ या नहीं?

इसके चलते और छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं।

खादी की नई ऊर्जा नई चेतना गाँव,गरीब और आत्मनिर्भर भारत की बदलती तस्वीर

विनोद कुमार सिंह तकियावाला

भारत की सभ्यता केवल महानगरों की चमक से नहीं,बल्कि गाँवों की मिट्टी की भीनी - भीनी सुगंध,कुटीर उद्योगों की आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा से निर्मित हुई है। यही कारण है कि जब भी हमारे समाने 'खादी' का नाम आता है,तो केवल एक वस्त्र नहीं,बल्कि भारतीय स्वाभिमान,स्वदेशी चेतना और आत्मनिर्भरता का पूरा इतिहास आँखों के सामने जीवंत हो उठता है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने जिस खादी को स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बनाया था,वही खादी आज विकसित भारत के आर्थिक अभियान की नई शक्ति बनती दिखाई दे रही है।हाल ही में जारी खादी ग्रामोद्योग आयोग(चङ्कढ्ढष्ट) की वार्षिक रिपोर्ट केवल सरकारी आँकड़ों का दस्तावेज नहीं है,बल्कि यह उस बदलते ग्रामीण भारत की कहानी है,जहाँ गाँव अब केवल कृषि आधारित जीवन का प्रतीक नहीं,बल्कि उत्पादन,रोजगार और उद्यमिता के नए केंद्र के रूप में उभर रहे हैं।रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 में खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 1.87 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गई।यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दशक पहले तक खादी को सीमित बाजार और पारंपरिक उत्पादों तक सीमित समझा जाता था।आज वही खादी वैश्विक बाजार में 'इको फ्रेंडली ', 'सस्टेनेबल' और 'हैंडमेड इंडिया' की पहचान बन रही है।

आप को स्पष्ट कर दे कि यह परिवर्तन अचानक नहीं आया। इसके पीछे वर्षों का सतत प्रयास, ग्रामीण कारीगरों की मेहनत, महिलाओं की भागीदारी और बदलती सरकारी नीतियों का समन्वय दिखाई देता है। 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल टू ग्लोबल' जैसे अभियानों ने खादी को नई ऊर्जा दी है।अब खादी केवल राजनीतिक प्रतीक या औपचारिक परिधान नहीं रही, बल्कि फैशन,लाइफस्टाइल और युवा पीढ़ी की पसंद का हिस्सा बनती जा रही है।आज दिल्ली, मुंबई,लखनऊ,अहमदाबाद और बेंगलुरु जैसे महानगरों के बड़े शोरूमों से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक खादी उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। खादी के वस्त्रों के साथ-साथ शहद, अगरबत्ती,साबुन,हस्तशिल्प,हर्बल उत्पाद,जैविक सामग्री और ग्रामीण उद्योगों से जुड़े अनेक उत्पाद बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बहुआयामी विस्तार का संकेत है।खादी की सबसे बड़ी शक्ति उसका 'रोजगार मॉडल' है। बड़े उद्योग जहां मशीन आधारित उत्पादन पर निर्भर होते हैं,वहीं खादी मानव श्रम और स्थानीय कौशल को केंद्र में रखती है। यही कारण है कि यह क्षेत्र करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करा रहा है।विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना को नई मजबूती दी है।गाँव की वह महिला, जो कभी केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित मानी जाती थी,आज चरखे,सिलाई,खाद्य प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन,अगरबत्ती निर्माण और हस्तशिल्प के माध्यम से परिवार की आर्थिक शक्ति बन रही है।इससे केवल आय नहीं बढ़ रही, बल्कि सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास भी मजबूत हो रहा है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (क्रल्थ्तक्क) के माध्यम से हजारों नई इकाइयों की स्थापना ने ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित किया है।यह योजना केवल ऋण वितरण का माध्यम नहीं, बल्कि गाँवों में छोटे उद्योगों की नई संस्कृति विकसित करने का अभियान बनती जा रही है।आज अनेक युवा नौकरी खोजने के बजाय स्वयं उद्यमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।खादी की बढ़ती सफलता भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को भी नई पहचान दे रही है। विश्व के अनेक देशों में भारतीय हस्तनिर्मित उत्पादों के प्रति आकर्षण बढ़ा है।खादी अब केवल कपड़ा नहीं,बल्कि भारतीय संस्कृति,प्रकृति प्रेम और सतत विकास का वैश्विक संदेश बन चुकी है।जिस समय पूरी दुनिया पर्यावरण संकट और मशीन आधारित अंधाधुंध उपभोग से जूझ रही है,उस समय खादी 'कम संसाधन, अधिक रोजगार और प्रकृति के संतुलन' का भारतीय मॉडल प्रस्तुत करती है।

शातिर सत्ताधीशों की सियासत का शिकार गोवंश

निर्मल रानी

भाजपा शासित राजस्थान में जैसलमेर में घटी एक अत्यंत संवेदनशील घटना ने देश के गौ भक्त समाज को झकझोर कर रख दिया। यहां के डंपिंग यार्ड में 500 से अधिक गायों के सड़े-गले शव और हड्डियां खुले में बिखरे हुए मिले पाये गये। इस जगह का दृश्य इतना भयावह व भीषण दुर्गंध पूर्ण था कि स्थानीय लोग और गौ-प्रेमी स्वभाविक रूप से इसे देखकर क्रोधित व विचलित हो गए। बताया जाता है कि इनमें से कई गायों की मौत ज़हरीला कचरा या पॉलीथिन खाने से हुई। जबकि इनमें बड़ी संख्या में ऐसी गायों के शव भी थे जिन्हें मृत पशुओं का निस्तारण करने वाले ठेकेदार ने इसी डंपिंग यार्ड में लाकर फेंक दिया था। भाजपा शासित राजस्थान में घटी इस दर्दनाक व शर्मनाक घटना ने सरकार व निजी गौ रक्ष संगठनों के गौ-रक्षा के दावों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि यह केवल किसी की लापरवाही मात्र का नहीं बल्कि मानवता और हिन्दू आस्था दोनों के ही अपमान से जुड़ा मामला है।

ग़ौरतलब है कि पिछले एक दशक से देश में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों को गौरक्षा के नाम पर मारा जा चुका है। मुहम्मद अख़लाक़ और पहलू ख़ान जैसे अनेक लोगों की हत्या की ख़बरें देश विदेश के मीडिया में प्रसारित होकर देश की बदनामी का कारण भी बन चुकी है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016-17 में इन्हीं कथित गौरक्षकों के संदर्भ में यह कह भी चुके हैं कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले 70-80 प्रतिशत लोग फ़र्ज़ी हैं, जो रात में ग़ैर-क़ानूनी काम करते हैं और दिन में गोरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मोदी ने कहा था कि उन्हें उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है जो गोरक्षा के नाम पर अपनी दुकानें खोलकर बैठ गए हैं। उन्होंने राज्य सरकारों से ऐसे लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करने और उनका डोज़ियर तैयार करने को भी कहा था। उस समय मोदी ने गोरक्षा के नाम पर हो रही हत्याओं की कड़ी निंदा भी की थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि गौ भक्ति के नाम पर लोगों की हत्या स्वीकार्य नहीं है।किसी को भी क़ानून अपने हाथ में लेने का हक़ नहीं है। उन्होंने असली गोरक्षकों को सलाह दी थी कि उन्हें गायों को प्लास्टिक खाने से बचाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि कटने से ज़्यादा गायें प्लास्टिक और कचरा खाने से मरती हैं।

गाय को लेकर बने देश के इसी तनावपूर्ण वातावरण में देश के मुस्लिम समाज ने उच्च स्तर पर कहीं फ़तवों से तो कहीं दिशा निर्देश जारी कर भारत के मुसलमानों को यह हिदायत जारी की है कि वे गाय की हत्या व गोमांस भक्षण यदि कहीं किया जा रहा है तो उससे पूरी तरह बाज़ आयें। यहाँ तक कि देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर अनेक प्रमुख मुस्लिम उलेमाओं और संगठनों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की वकालत की है। इनके अनुसार ऐसा करने से देश में नफ़रत और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी, और बहुसंख्यक समाज की आस्था का सम्मान होगा। कई इस्लामी विद्वानों और मौलानाओं का तो स्पष्ट मत है कि इस्लाम में गौ मांस खाने को सख़्ती से मना किया गया है। पैग़ंबर मोहम्मद साहब के कथनों का हवाला देते हुए मौलानाओं द्वारा यह बताया गया है कि गाय के मांस में बीमारी है और उसके दूध में शिफ़ा अर्थात राहत है। अनेक मुस्लिम संगठनों ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई है, ताकि गाय को लेकर होने वाली सांप्रदायिक राजनीति पर पूर्ण विराम लग सके।

परन्तु हिंदूवादी संगठनों द्वारा गौ हत्या को लेकर केवल मुसलमानों पर निशाना साधने वालों को इसी सिक्के के दूसरे पहलू को समझना भी ज़रूरी है। इस सन्दर्भ में पिछले दिनों हुए असम चुनावों के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का वह बयान क़ाबिल -ए -ग़ौर है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार लोगों के घर के अंदर गोमांस खाने अर्थात निजी खान-पान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। उन्हें इसे खाने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन इसे सार्वजनिक तौर पर खाने के बजाय अपने घरों के अंदर खाना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक रूप से या धार्मिक स्थलों के आसपास इसका सेवन क़ानूनन और सामाजिक भावनाओं के ख़िलाफ़ है। सवाल यह है कि जब गोवध होगा तभी तो गोमांस घरों में भी खाया जा सकेगा ? दूसरे यह कि केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों व जातियों के लोगों द्वारा भी बड़ी संख्या में गौमांस भक्षण किया जाता है तभी वोट बैंक के मद्देनज़र यह बयान मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया। इसी तरह अप्रैल 2017 में केरल के मल्लापुरम लोकसभा उपचुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार एन. श्रीप्रकाश ने मतदाताओं से वादा किया था कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता वाले बीफ़ की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे और साफ़-सुथरे बूचड़ख़ाने खुलवाएंगे। जबकि अभी पिछले दिनों बंगाल में सत्ता में आई भाजपा सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में क़ानूनन केवल उसी गोवंश (गाय) का वध नहीं किया जा सकता जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो। इस कुतर्क के अनुसार क्या 14 वर्ष से ऊपर की गाय गौ माता की श्रेणी से बाहर हो जाती है?

भारत सरकार में संसदीय कार्य व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का 2015 में दिया गया वह बयान पूरे देश को याद ही होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ और गोमांस खाता हूँ। क्या कोई मुझे ऐसा करने से रोक सकता है? उनका तर्क था कि भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत से लोग बीफ़ खाते हैं और किसी के खान-पान की आदतों या जीवनशैली को उन पर थोपा नहीं जा सकता। साथ ही उसी समय उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि भारत विविधताओं का देश है। जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां उनकी आस्था और भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। गोरक्षा पर राजनीति करने वाली सरकार किरेन रिजिजू जैसे गौ मांस भक्षक को मंत्री बनाकर किस आधार पर गोरक्षा की बात कर सकती है ? उधर यही भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बांड के ज़रिए भारत की सबसे बड़ी बीफ़ निर्यातक कंपनियों से लगभग प्रत्येक चुनावों में करोड़ों का चंदा वसूलती है। इसी सत्ता संरक्षण की वजह से 2014 के बाद यानी भाजपा के शासनकाल में भारत का कुल बीफ़ निर्यात काफ़ी बढ़ चुका है। परन्तु स्वयंभू गोरक्षकों को गोहत्या को बढ़ावा देने व इसके पक्ष में तर्क देने वालों से कोई शिकायत नहीं है बल्कि आश्चर्य है कि इनकी सारी दुश्मनी व शिकायत केवल मुसलमानों से ही है ? समझा जा सकता है कि गोवंश की सुरक्षा किसी धर्म जाति से जुड़ा विषय नहीं बल्कि वास्तव में गोवंश शातिर सत्ताधीशों की सियासत का शिकार है।

क्या 'कॉकरोच जनता पार्टी ', उक्त लक्ष्य को रोक पाएगी ?

भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में यदि किसी एक दल की रणनीतिक निरंतरता, संगठनात्मक अनुशासन और विस्तारवादी राजनीतिक भूख सबसे स्पष्ट दिखाई देती है, तो वह भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पश्चिम बंगाल में भाजपा की उल्लेखनीय सफलता को एक प्रकार की 'वैचारिक घर-वापसी' भी कहा जा रहा है। हालांकि यह प्रश्न अभी भी राजनीतिक गलियारों में 'चाय की प्याली में तूफान' बना हुआ है कि बंगाल में आया परिवर्तन वास्तव में 'बदला नहीं बदलाव' था, या 'बदले की भावना से उपजा बदलाव '? राजनीति में अक्सर 'दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है ', इसलिए विपक्ष इस परिणाम को सहजता से स्वीकार करने की स्थिति में नहीं दिखता। प्रधानमंत्री मोदी का बढ़ता आत्मविश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी आत्मविश्वास बैरकपुर की अंतिम चुनावी सभा में स्पष्ट रूप से व्यक्ति उनके इस कथन के साथ हुआ– '4 मई के बाद बंगाल में भाजपा के शपथ ग्रहण समारोह में आना ही है '।

यद्यपि 'कांग्रेस-विहीन भारत' का लक्ष्य अभी पूर्णतः साकार नहीं हुआ, किंतु भाजपा का 'वन नेशन, वन पार्टी' की दिशा में बढ़ना अब केवल विपक्ष का आरोप नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का विषय बन चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा ने 'लोहे को गर्म देखकर चोट करना' सीख लिया है। लोकसभा चुनाव परिणाम से मिला सबक। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के सत्ता में आने के बावजूद भाजपा को अपेक्षित बहुमत न मिलना पार्टी के लिए 'आसमान से गिरकर खजूर में अटकने' जैसा क्षण अवश्य था, किंतु यही झटका भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए आत्ममंथन का अवसर बन गया। गृह मंत्री अमित शाह की 'माइक्रो मैनेजमेंट' शैली, बूथ स्तर तक की रणनीति और संघ परिवार के जमीनी नेटवर्क ने भाजपा को पुनः राजनीतिक पटरी पर लौटा दिया। भाजपा ने सिद्ध किया कि वह हार को 'ठोकर' नहीं, बल्कि 'सीढ़ी' बनाना जानती है।

विधानसभा चुनावों में अप्रत्याशित सफलता।

लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जिस प्रकार बाउंस बैक किया, उसने राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया। चार राज्यों के आसीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नवीन पटनायक एमके स्टालिन और ममता बनर्जी को अपने ही गढ़ में हार का सामना करना पड़ा। राजनीति में कहा जाता है– 'जो सोता है, वही खोता है '। यह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि भाजपा चुनाव को इवेंट नहीं निरंतर प्रक्रिया मानकर चलती है।

भाजपा चुनाव को 'पाँच साल का उत्सव' नहीं, बल्कि '24म7 चलने वाली राजनीतिक साधना' मानती है। यही कारण है कि शपथ ग्रहण के अगले दिन से ही अगले चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो जाती है।

विपक्ष बनाम संगठनात्मक अनुशासन।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने संघर्षशील नेता की छवि बनाए रखी, किंतु भाजपा का संगठनात्मक ढाँचा और विस्तार अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ। दूसरी ओर राहुल गांधी की सीमित चुनावी सक्रियता ने विपक्ष की रणनीतिक कमजोरी को उजागर कर दिया। राजनीति में एक पुरानी कहावत है– 'जितना पसीना अभ्यास में बहाओगे, उतना खून मैदान में नहीं बहेगा।' भाजपा ने इस सिद्धांत को व्यवहार में उतारा है, जबकि विपक्ष कई बार 'नौ दिन चले अढ़ाई कोस' की स्थिति में दिखाई दिया। एंटी-इनकंबेंसी को अवसर में बदलना। सामान्यतः लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली सरकारों के विरुद्ध एंटी-इनकंबेंसी पैदा होती है, किंतु भाजपा ने गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इस धारणा को सफलता पूर्वक चुनौती दी।

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बढ़ती आशंकाएं

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया हालिया फैसला चुनाव आयोग के अधिकारों की पुष्टि करता है। इसके साथ ही इस फैसले से कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अदालत ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को वैधानिक अधिकारों के दायरे में माना, परंतु सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई उन आशंकाओं और दस्तावेजी आपत्तियों पर फैसला स्पष्ट नहीं है, जिनका सीधा संबंध करोड़ों मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है।

सनत जैन

यही कारण है, यह विवाद समाप्त होने के बजाय और अधिक गहराने की आशंका पैदा होने लगी है। एसआईआर प्रक्रिया का मूल उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और सही करना बताया गया था। लेकिन व्यवहार में अनेक ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें वैध दस्तावेज रखने वाले नागरिकों के नाम भी मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। बीएलओ रिटर्निंग अधिकारी के अधिकार भी चुनाव आयोग ने स्वयं इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। मतदाता शुद्धिकरण के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के पोर्टल से बिना बीएलओ, बिना रिटर्निंग अधिकारी की जानकारी के बिना भौतिक सत्यापन के करोड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अलग कर दिए गए। जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में मौजूद थे। उनके माता-पिता के नाम भी 2003 की मतदाता सूची में थे। उन्हें भी विभिन्न तकनीकी कारणों के आधार पर सूची से बाहर कर दिया गया। इससे प्रश्न उठना स्वाभाविक है, वर्षों से मतदान कर रहे नागरिकों की वैधता पर अचानक संदेह कर उनका नाम कैसे मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जन्मस्थली नागरिकता और मतदाता सूची की स्थिरता और विश्वसनीयता का आधार क्या रहेगा?

स्थिति की गंभीरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक लगभग 5.50 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की बात सामने आ रही है। अकेले पश्चिम बंगाल में लगभग एक करोड नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं, जबकि करीब 28 लाख लोगों ने दस्तावेजों के साथ ट्रिब्यूनल में अपील कर रखी है। यह केवल चुनाव आयोग के अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया में जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला भी है। इतनी बड़ी संख्या मतदाता सूची से नाम काटना प्रशासनिक त्रुटि का संकेत नहीं है। बल्कि यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े नागरिकों के अधिकार का प्रश्न है। एसआईआर की प्रक्रिया में यदि करोड़ों लोगों के संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहे हैं। इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्पष्ट नहीं है। विधि विशेषज्ञों का कहना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया, जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से

हटाए गए हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित होगी। बिहार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं है उन्हें अभी तक जो सरकारी सुविधा मिल रही थी, वह बंद करने का निर्णय लिया है। इसमें जो मुसलमान मतदाता थे, उन्हें बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बताकर उनके लिए अलग से डिटेंशन सेंटर बनाकर रखने की बात की जा रही है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकार उन्हें अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है। इसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है जो धार्मिक धुव्रीकरण की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग को लेकर कई गंभीर किस्म के आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की नियुक्ति कानून की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। एसआईआर के जो नियम ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग ने तैयार किये, हर राज्य में अलग-अलग तरह के नियम बनाए गए। इसको लेकर यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई महीने तक प्रक्रिया को लेकर सुनवाई की, लेकिन इस संबंध में कोई भी स्पष्टता वाला आदेश नहीं आया है। यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटता है। उसके बाद उसे धार्मिक आधार पर संदेह की दृष्टि से भेदभाव किया जाता है, तो यह केवल चुनावी प्रक्रिया का विषय नहीं रह जाता। सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न बन जाता है।

लोकतंत्र केवल मतदान कराने की व्यवस्था नहीं है। नागरिकों के संवैधानिक अधिकार और लोकतंत्र के विश्वास पर टिका है। जब करोड़ों लोगों को अपने जन्म और अस्तित्व तथा नागरिक अधिकारों के लिए दस्तावेजों के होते हुए भी प्रमाण देने पड़ें। तब स्वाभाविक रूप से नागरिकों में असुरक्षा और असंतोष बढ़ना तय है। यही कारण है कि विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा आशंका व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय में यह मुद्दा एक बड़े आंदोलन और राजनीतिक टकराव का कारण बन सकता है। कानून व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की जाने लगी है। जिस तरह से देश में स्थितियां बदल रही हैं, ऐसे समय पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दूरगामी परिणाम देने वाला बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानूनी दृष्टि से चुनाव आयोग की शक्तियों को मजबूत करता है। लोकतांत्रिक दृष्टि से इस फैसले में अनेक प्रश्न अनुत्तरित हैं।

आवश्यकता इस बात की है, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, न्यायपालिका मिलकर ऐसी पारदर्शी व्यवस्था विकसित करे, जिसमें किसी भी वैध नागरिक को तकनीकी कारणों से अपने मताधिकार और नागरिक अधिकारों से वंचित न होना पड़े। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता का विश्वास है, कानून का पालन तभी तक संभव है जब तक लोगों को उस पर विश्वास हो। उस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की है। सभी संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज से जनता के बीच में यह विश्वास पैदा होता है। तभी नागरिक कानून और नियमों का पालन करते हैं। यदि विश्वास खत्म हो जाता है। जो स्थिति अभी बनी है उसमें एक भीड खड़ी होती है। जो स्वयं न्याय करने लगती है। तब नियम कानून और शासन व्यवस्था का कोई महत्व नहीं रह जाता है। भीड़ में असाधारण शक्ति होती है।

पहाड़ों के बीच पहुंची विकास की धारा, ठोरगी में हर घर तक पहुंचा स्वच्छ पानी

जहां कभी पानी के लिए था संघर्ष, वहां अब जल जीवन मिशन बना उम्मीद की किरण

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। दुर्गम पहाड़ियों, कच्चे रास्तों और सीमित संसाधनों के बीच बसे ग्राम पंचायत खोहरा के आश्रित ग्राम ठोरगी में आज विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है कभी पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष करने वाला यह गांव अब जल जीवन मिशन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्राप्त कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना ने ग्रामीणों के जीवन में व्यापक बदलाव लाते हुए गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी हैं एक समय था जब ठोरगी के लोगों की सुबह पानी की तलाश से शुरू होती थी। गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे कई किलोमीटर दूर नदी, कुएं और हैंडपंपों तक पहुंचकर पानी

लाने को मजबूर थे। पहाड़ी और दुर्गम रास्तों से भारी बर्तन उठाकर पानी लाना ग्रामीणों के लिए रोजाना की कठिन चुनौती थी। गर्मी के दिनों में हालात और भी गंभीर हो जाते थे, जब जल स्रोत सूखने लगते थे और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में सुदृढ़ पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया गया है तथा 10 हजार लीटर क्षमता वाली पानी टंकी का निर्माण किया गया है। मोटर पंप के माध्यम से नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की गई है, जिससे अब गांव के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल आसानी से पहुंच रहा है। जहां पहले पानी लाने में घंटों का समय लगता था, वहीं अब घरों के पास पानी उपलब्ध होने से ग्रामीणों का समय और श्रम दोनों बच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस योजना ने केवल पानी की समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि सामाजिक और स्वास्थ्य स्तर पर भी सकारात्मक परिवर्तन लाया है। महिलाओं को भारी राहत मिली है बच्चों की पढ़ाई अब प्रभावित नहीं होती और बुजुर्गों को कठिन चढ़ाई से मुक्ति मिली है स्वच्छ पेयजल मिलने से जलजनित बीमारियों में भी कमी आई है। ठोरगी में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की सक्रिय भूमिका इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। समिति के सदस्य नियमित रूप से जलापूर्ति व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं और ग्रामीणों को जल संरक्षण तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। गांव में साफ-सफाई जल स्रोतों की सुरक्षा और पानी के सदुपयोग को लेकर लोगों में नई सोच विकसित हुई है आज ठोरगी केवल एक गांव नहीं बल्कि सामुदायिक सहभागिता जल संरक्षण और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जीवंत मिसाल बन चुका है। दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे इस छोटे से गांव ने यह साबित कर दिया है कि मजबूत इच्छाशक्ति और जनभागीदारी के माध्यम से विकास की धारा सबसे कठिन रास्तों तक भी पहुंच सकती है।

डायल-112 जवानों की संवेदनशीलता से सुरक्षित मिला घर से भटका बालक

मीडिया ऑडिटर, भोपाल (निप्र)। उज्जैन जिले के थाना चिंतामन गणेश क्षेत्र में डायल-112 जवानों की संवेदनशीलता और तत्परता से मानसिक रूप से अस्वस्थ एक 10 वर्षीय बालक को सुरक्षित संरक्षण में लेकर थाना पहुंचाया गया। समय रहते की गई पुलिस की इस मानवीय कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना की जा रही है जानकारी के अनुसार 26 मई को राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112 भोपाल को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना चिंतामन गणेश क्षेत्र के अंतर्गत कंदरिया चौराहा के पास एक मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक अकेला घूमता हुआ मिला है बालक घर का रास्ता भटक गया था और उसे तत्काल पुलिस सहायता की आवश्यकता थी सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम द्वारा चिंतामन गणेश थाना क्षेत्र में तैनात डायल-112 वाहन को तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया। डायल-112 स्टाफ आरक्षक सागर सिंह एवं पायलट लाल सिंह मौके पर पहुंचे और बालक को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया पुलिस जवानों ने बालक से उसके घर और परिजनों के बारे में जानकारी

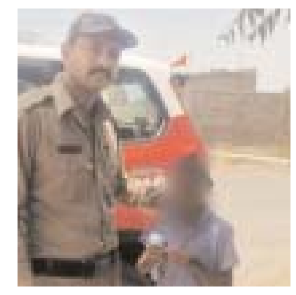

प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वह कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। इसके बाद डायल-112 टीम ने मानवता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बालक को वाहन में बैठाकर आसपास के क्षेत्रों में परिजनों की तलाश शुरू की। स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन बच्चे के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी काफी प्रयासों के बाद भी परिजनों का पता नहीं चलने पर डायल-112 टीम द्वारा बालक को सुरक्षित थाना चिंतामन गणेश पहुंचाया गया, जहां आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बालक के परिजनों की तलाश जारी है और बच्चे की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

करैरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 194 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार 48 लाख रुपए का माल जब्त, हुंडई क्रेटा कार सहित सात बोरियों में मिला गांजा

मीडिया ऑडिटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले की करैरा पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 194 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक हुंडई क्रेटा कार भी जब्त की है बरामद कुल माल की कीमत करीब 48 लाख रुपए आंकी गई है जिसमें लगभग 38 लाख रुपए मूल्य का गांजा शामिल है करैरा एसडीओपी डॉ. आयुष जाखड़ (आईपीएस) ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के नशा मुक्ति अभियान के तहत जिलेभर में लगातार कार्रवाई

की जा रही है। इसी क्रम में थाना प्रभारी विनोद छावई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पिछोर-बामौर रोड की ओर से एक सिल्वर रंग की क्रेटा कार में अवैध गांजा लेकर दो लोग करैरा कस्बे की ओर आने वाले हैं सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और पाल कॉलोनी के पास घेराबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद बताए गए नंबर की सिल्वर रंग की हुंडई क्रेटा कार वहां पहुंची, जिसे पुलिस ने रोककर तलाशी ली कार में सवार आरोपियों ने अपने नाम नीरज राय निवासी राय मोहल्ला टीला करैरा तथा मानसिंह विश्वकर्मा निवासी नयाताल टीला करैरा बताए। तलाशी के दौरान कार की पिछली सीट पर सात प्लास्टिक की बोरियां रखी मिलीं। जब पुलिस ने बोरियां खोलीं तो उनमें सफेद पॉलीथिन पैकेट पाए गए, जिनमें सूखी पत्तियां और गांजा भरा हुआ था। प्रत्येक बोरी में 28 पैकेट रखे गए थे पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि बोरियों में गांजा भरा हुआ है लेकिन वे इसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके पुलिस ने मौके पर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया करैरा थाने में आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 346/26 के तहत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई से भड़का जनआक्रोश, पानी टंकी के सामने कांग्रेस का धरना

मनेन्द्रगढ़ में दूषित जलापूर्ति के खिलाफ पार्षदों और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, स्वच्छ पानी मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। शहर में लगातार गंदे, बदबूदार और पीले पानी की सप्लाई से लोगों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है नगर पालिका क्षेत्र के कई वार्डों में दूषित पानी पहुंचने से नाराज कांग्रेस पार्षदों और पदाधिकारियों ने बुधवार को पानी टंकी के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जल व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की। धरने पर बैठे पार्षदों का कहना है कि पिछले कई दिनों से शहर के विभिन्न

वार्डों में नलों के माध्यम से पीला और बदबूदार पानी सप्लाई किया जा रहा है इससे आम नागरिकों को पीने के स्वच्छ पानी के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों का आरोप है कि दूषित पानी के कारण बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है लेकिन नगरपालिका प्रशासन इस गंभीर समस्या को लेकर उदासीन बना हुआ है कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वार्डों के रहवासी लगातार शिकायत कर रहे हैं बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी केवल आश्वासन देकर मामले को टाल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घरों में साफ पानी की जगह गंदा और बदबूदार पानी पहुंच रहा है जिससे खासकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है धरना प्रदर्शन के दौरान पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि जब तक शहरवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की नियमित सप्लाई शुरू नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा वहीं मनेन्द्रगढ़ नगरपालिका प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है।

स्वच्छता अभियान को गांवों में मिल रही नई गति बरबसपुर और सिरौली में प्लास्टिक अपशिष्ट बिक्री व जियो टैगिंग कार्य तेज

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायतों में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर लगातार प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं इसी क्रम में ग्राम पंचायत बरबसपुर एवं सिरौली में स्वच्छता ग्राहियों द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण और जियो टैगिंग का कार्य किया गया।

बरबसपुर में स्वच्छता ग्राहियों ने बेचा प्लास्टिक अपशिष्ट: ग्राम पंचायत बरबसपुर के स्वच्छता ग्राहियों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई चनवारीडांड के स्वच्छता ग्राहियों को 15 किलोग्राम सफेद पन्नी, 46 किलोग्राम रंगीन पन्नी एवं 8 किलोग्राम प्लास्टिक बोतलें विक्रय की गईं। इस दौरान ग्राम पंचायत सचिव भी उपस्थित रहे।

सूची ऐप से किया गया जियो टैगिंग कार्य: बरबसपुर ग्राम पंचायत में सूची ऐप के माध्यम से

आंगनबाड़ी, स्कूल, सामुदायिक शौचालय सहित अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों का जियो टैगिंग कार्य भी किया गया, जिससे स्वच्छता एवं आधारभूत सुविधाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग को मजबूती मिलेगी।

सिरौली और नागोई में भी चला स्वच्छता अभियान: वहीं ग्राम पंचायत सिरौली के ग्राम नागोई में स्वच्छता ग्राहियों द्वारा सफेद पन्नी, रंगीन पन्नी और प्लास्टिक बोतलों का संग्रहण कर उन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई चनवारीडांड के स्वच्छता ग्राहियों को बेचा गया।

कई गांवों में सार्वजनिक परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग: ग्राम पंचायत सिरौली, नागोई, पिपरिया एवं कठौतिया में सूची ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, सामुदायिक शौचालय और नाडेप संरचनाओं का जियो टैगिंग कार्य किया गया।

स्वच्छता और डिजिटल मॉनिटरिंग को मिल रही मजबूती: प्रशासन का कहना है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और डिजिटल जियो टैगिंग के माध्यम से गांवों में स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा रहा है इससे न केवल स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सार्वजनिक परिसंपत्तियों की नियमित निगरानी भी सुनिश्चित हो सकेगी।

बकरीद अवकाश के चलते 28 मई का सुशासन तिहार शिविर अब 29 मई को होगा आयोजित

ग्राम पंचायत बड़गांवखुर्द में प्रस्तावित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर की तिथि में संशोधन

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 28 मई 2026 को 'ईद-उल-जुहा (बकरीद)' पर्व के अवसर पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किए जाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत आयोजित होने वाले एक महत्वपूर्ण शिविर की तिथि में आंशिक संशोधन किया गया है जारी आदेश के मुताबिक जनपद पंचायत भरतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़गांवखुर्द में 28 मई 2026 को प्रस्तावित जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर अब 29 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल शिविर की तिथि में परिवर्तन किया गया है जबकि आयोजन स्थल एवं अन्य सभी व्यवस्थाएं पूर्ववत बनी रहेंगी उल्लेखनीय है कि 'सुशासन तिहार 2026' के तहत जिले भर में विभिन्न स्थानों पर जनसमस्याओं के निराकरण हेतु शिविरों

का आयोजन किया जा रहा है जहां आम नागरिक अपनी समस्याएं एवं शिकायतें सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। इन शिविरों के माध्यम से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा जारी संशोधित आदेश में कहा गया है कि बकरीद के सार्वजनिक अवकाश को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि आम नागरिकों एवं अधिकारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुशासन तिहार के अंतर्गत जिले के अन्य सभी शिविर पूर्व निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे प्रशासन ने संबंधित विभागीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे संशोधित तिथि 29 मई 2026 को आयोजित होने वाले शिविर में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु लाभ उठाएं यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

शिवपुरी के करसेना गांव में 10 साल से जल संकट चक्काजाम और चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी

मीडिया ऑडिटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले की ग्राम पंचायत करसेना में ग्रामीण पिछले 20 वर्षों से गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। समस्या का समाधान न होने पर ग्रामीणों ने 10 दिनों के भीतर स्थायी हल नहीं मिलने पर हाइवे पर चक्काजाम करने की चेतावनी दी है एक किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर ग्रामीण गांव की महिलाएं और पुरुष प्रतिदिन लगभग एक किलोमीटर दूर स्थित हैंडपंप से पैदल पानी लाने को विवश हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया है।

छोटी पानी की टंकी और खराब मोटर बनी परेशानी: ग्रामीणों के अनुसार, गांव में बनी सरकारी पानी की टंकी छोटी है, जिससे पूरे गांव की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती। नल-जल योजना के तहत बिछाई गई लगभग 2 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भी मोटर के बार-बार खराब होने के कारण अनुपयोगी साबित हो रही है इस वजह से ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है जिससे भीषण गर्मी में जनजीवन और पशु प्रभावित हो रहे हैं साथ ही दूषित पानी से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है ग्रामीणों ने अपनी मांगों में एससी-एसटी बस्ती के लगभग 100 से 150 घरों के लिए सरकारी बोर में 15 एचपी की नई मोटर, 1000 मीटर पाइपलाइन और कुएं से जुड़ी वैकल्पिक जल व्यवस्था की स्वीकृति शामिल की है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एक नए बोरवेल और पानी के टैंकर की व्यवस्था की भी मांग की है, ताकि गांव में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित हो सके पंचायत सचिव पर लापरवाही के आरोप ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है।उनका कहना है कि सचिव गांव की समस्याओं को सुनने से बचते हैं और खुद को शिवपुरी कार्यालय में पदस्थ बताकर टालमटोल करते हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से वर्तमान सचिव को हटाकर नए सचिव की नियुक्ति की मांग की है।

मध्यप्रदेश पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एक सप्ताह में 80 लाख से अधिक के मादक पदार्थ जब्त

प्रदेशभर में चलाए गए अभियान में गांजा, स्मैक, अफीम, डोडाचूरा और प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद

मीडिया ऑडिटर, भोपाल (निप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशभर में अवैध मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न जिलों में चलाए गए विशेष अभियानों के दौरान पुलिस ने विगत एक सप्ताह में लगभग 80 लाख रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है मंदसौर जिले की नारायणगढ़ पुलिस ने पुलिस पर फायर कर भागने वाले अंतर्राज्यीय डोडाचूरा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 252 किलोग्राम डोडाचूरा, एक देशी पिस्टल, राउंड, मोबाइल फोन और कार सहित करीब 20 लाख 51 हजार रुपए की संपत्ति जब्त

की। वहीं शामगढ़ पुलिस ने संतरे के बगीचे में छिपाकर लगाए गए 384 गांजा पौधे बरामद किए दूसरी कार्रवाई में 68 ग्राम एमडी ड्रग्स पाउडर और 5 किलोग्राम डोडाचूरा जब्त किया गया गुना जिले में मृगवास थाना पुलिस ने राजस्थान से अफीम तस्करी कर रहे दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर 1 किलो 10 ग्राम अफीम और मोटरसाइकिल जब्त की। वहीं दूसरी कार्रवाई में 10 किलो 157 ग्राम गांजा और दो मोटरसाइकिलों के साथ चार तस्करों को पकड़ा गया। दोनों मामलों में करीब 18 लाख 20 हजार रुपए की संपत्ति जब्त हुई शिवपुरी जिले के करैरा थाना पुलिस ने दो आरोपियों को 43.06 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8 लाख 60 हजार रुपए बताई गई है। राजगढ़ जिले में ऑपरेशन 'शुद्धि के तहत भोजपुर पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाइयों में कुल 81.50 ग्राम स्मैक जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच ने ट्रेन से गांजा सप्लाई करने पहुंचे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 महिलाओं सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लगभग 36 किलो गांजा बरामद किया गया। दूसरी कार्रवाई में 7 किलो 670 ग्राम गांजा भी जब्त किया गया जीआरपी शहडोल ने ट्रेन में तस्करी कर ले जाए जा रहे 41 किलो गांजा को जब्त किया, जबकि दमोह जिले की पटेरा पुलिस ने अलग-अलग मामलों में 13 किलो से अधिक गांजा बरामद किया। मैहर, नरसिंहपुर और अनूपपुर जिलों में भी स्मैक और गांजा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया सीधी जिले में ऑपरेशन 'प्रहार 2.0' के तहत थाना जमोड़ी पुलिस ने 3 हजार 480 प्रतिबंधित ऑनरेक्स कफ सिरप जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख 96 हजार रुपए आंकी गई है। वहीं रीवा जिले में सगरा पुलिस ने 115 शीशी अवैध ऑनरेक्स कफ सिरप और स्कूटी जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया मध्यप्रदेश पुलिस ने कहा है कि समाज को नशामुक्त बनाने और युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

खंडवा में ब्रेक फेल होने पर टैंकर में घुसा ट्रक

केबिन में फंसे ड्राइवर-क्लीनर को आधे घंटे बाद निकाला, दोनों की हालत गंभीर

मीडिया ऑडीटर, खंडवा (निप्र)। खंडवा जिले के इंदौर-एदलाबाद नेशनल हाईवे पर मंगलवार दोपहर ट्रक के ब्रेक फेल हो गए और ट्रक एक टैंकर में जा घुसा। पंधाना थाना क्षेत्र की बोरगांव चौकी अंतर्गत एक निजी होटल के सामने यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर टैंकर से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और चालक व क्लीनर केबिन में बुरी तरह फंस गए।

तेज रफ्तार में था ट्रक: हादसा दोपहर करीब 2 बजे हुआ। दुर्घटना में ट्रक चालक नासिर खान और क्लीनर राशिद खान घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक बाधित रहा।

पुलिस के मुताबिक, ट्रक तेज रफ्तार में था। इसी दौरान अचानक उसके ब्रेक फेल हो गए, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक सीधे सामने खड़े टैंकर से टकरा गया। टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी।

आधे घंटे की मशक्कत के बाद निकाले गए घायल: सूचना मिलते ही बोरगांव चौकी प्रभारी अविनाश भोपले पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद ट्रक का दरवाजा और केबिन का मुड़ा हुआ हिस्सा काटकर दोनों घायलों को बाहर निकाला गया। इसके बाद डायल-100 वाहन की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंधाना पहुंचाया गया।

हाईवे पर बढ़ रहे हादसों से लोगों में चिंता: स्थानीय लोगों का कहना है कि इंदौर-एदलाबाद नेशनल हाईवे पर लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। भारी वाहनों की तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग, तकनीकी खराबी और लापरवाही के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों ने हाईवे पर नियमित वाहन जांच, स्पीड कंट्रोल और सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया।

छतरपुर में पानी के लिए सड़क पर उतरे ग्रामीण

दो साल से सूखी पाइपलाइन,महिलाओं ने पानी का बर्तन रखकर रास्ता जाम किया

मीडिया ऑडीटर, छतरपुर (निप्र)। छतरपुर जिले के बक्सवाहा जनपद की मडदेवरा पंचायत में गहराते पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। बुधवार को गांव की महिलाओं और अन्य ग्रामीणों ने सड़क पर पानी के बर्तन रखकर रास्ता जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वे पिछले दो वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और तत्काल पानी उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे।

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में नल-जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन पिछले दो सालों से उनमें पानी नहीं आया है। उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं का प्रचार तो खूब होता है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। गांव में पेयजल की समस्या लगातार बनी हुई है और जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि उन्हें दैनिक उपयोग के खाने-पीने तक के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। पानी के लिए उन्हें रोजाना दूर-दूर तक भटकना पड़ता है।

ग्रामीणों के अनुसार, उन्होंने कई बार पंचायत के सरपंच और सचिव से शिकायत की, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। उनका कहना है कि अब उन्हें हर छोटी-बड़ी समस्या के लिए कलेक्टर कार्यालय जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द पेयजल संकट का स्थायी समाधान करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द पानी की व्यवस्था नहीं की गई, तो उनका आंदोलन और उग्र हो सकता है। इस प्रदर्शन के कारण सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा।

रायसेन में 116 बसों पर चालानी कार्रवाई

फायर सेफ्टी-ओवरलोडिंग में सबसे ज्यादा उल्लंघन; 7 दिन तक चला अभियान

मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले में यातायात पुलिस ने यात्री बसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर 21 से 27 मई तक चले इस अभियान में जिले में पंजीकृत और यहां से गुजरने वाली करीब 150 बसों की जांच की गई। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाली 116 बसों पर चालानी कार्रवाई की गई है। फायर सेफ्टी और ओवरलोडिंग में सबसे ज्यादा चालान अभियान में सर्वाधिक 43 चालान बसों में फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट और फर्स्ट एड बॉक्स न होने पर बनाए गए। वहीं, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने (ओवरलोडिंग) के मामले में 37 यात्री बसों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा एक बस बिना वैध बीमा के मिली, जबकि अन्य वाहनों पर यातायात की विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना लगाया गया।

लोडिंग वाहन से पकड़ाया 150 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा

राजस्थान के नागौर के दो तस्कर लेकर जा रहे थे,फोरलेन पर घेराबंदी कर पकड़ा

मीडिया ऑडीटर, (निप्र)। रतलाम,एजेंसी। रतलाम पुलिस ने मंगलवार को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 किलोग्राम डोडाचूरा जब्त किया है। जिले की रिंगनोद थाना पुलिस और माननखेड़ी चौकी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में करीब 3 लाख रुपए कीमत का डोडाचूरा पकड़ा। पुलिस ने फोरलेन पर घेराबंदी कर एक 407 लोडिंग वाहन को रोका, जिसमें दो आरोपी अवैध मादक पदार्थ लेकर जावरा की ओर जा रहे थे।

तलाशी लेने पर मिला 150 किलो माल: संदिग्ध लोडिंग वाहन आने पर रोक कर तलाशी। तलाशी के दौरान वाहन में 150 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद हुआ। मौके पर वाहन में सवार जीवनराम (48) पिता परमाराम विश्नोई, निवासी पालडीमेस थाना गच्छीपुरा जिला नागौर (राजस्थान) व सुखाराम (30) पिता बल्लाराम विश्नोई निवासी रेण थाना मेडता जिला नागौर (राजस्थान) को एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया।

पुलिस ने पिकअप वाहन को भी जप्त कर लिया है। जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से डोडाचूरा के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के बारे में पूछताछ की जा रही है।

सीहोर में हैंडपंप सूखे, एक पर निर्भर सैकड़ों परिवार

ग्रामीण काम छोड़कर ढो रहे पानी, पीएचई-जल निगम पर लापरवाही का आरोप

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। सीहोर के डोबरा गांव में भीषण जल संकट गहरा गया है। गांव के सैकड़ों परिवार पानी के लिए जूझ रहे हैं और उन्हें अपने जरूरी काम छोड़कर घंटों हैंडपंप पर बिताने पड़ रहे हैं। ग्रामीण कई किलोमीटर दूर से साइकिल और बाइक पर पानी लाने को मजबूर हैं। लगभग एक हजार की आबादी वाले इस गांव में कुल 10 सरकारी हैंडपंप हैं, जिनमें से 9 पूरी तरह सूख चुके हैं। एकमात्र चालू हैंडपंप में भी जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जिससे रुक-रुक कर पानी आता है। डोबरा कॉलोनी के गरीब परिवार इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बोरिंग कराने की अनुमति नहीं देती। करीब सौ परिवार पूरी तरह सरकारी हैंडपंप पर निर्भर हैं।

गांव में नर्मदा पाइपलाइन बिछाने का काम भी धीमी गति से चल रहा है। यह परियोजना वर्ष 2024 में स्वीकृत हुई थी, लेकिन पूरे गांव में अभी तक लाइन नहीं बिछाई जा सकी है। टंकी निर्माण का कार्य भी अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार की मनमानी के कारण काम में देरी हो रही है, जिससे उन्हें नर्मदा जल का इंतजार है। जल संकट के बावजूद, पीएचई विभाग ने गांव में नए बोरिंग पर रोक लगा दी है, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के पास लाखों रुपये का फंड है, लेकिन जनपद पंचायत और पीएचई विभाग ने उन्हें नए बोरिंग या हैंडपंप लगाने से यह कहकर रोक दिया है कि गांव में जल निगम द्वारा नर्मदा लाइन बिछाने का काम चल रहा है। इस संबंध में पीएचई विभाग के ईई प्रदीप सक्सेना ने बताया कि इस वर्ष शासन से कम लक्ष्य मिले हैं। उन्होंने कहा कि यदि बहुत अधिक आवश्यकता होगी, तभी नए बोरिंग कराए जाएंगे।

बढ़ते तापमान के दृष्टिगत लू से बचाव हेतु सावधानी बरतने की अपील

मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बढ़ते हुए तापमान से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रवभावों से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इस संबंध में जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रभारी अधिकारियों को सतत निगरानी एवं उपचार के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य संस्थाओं के अधिकारियों को आने वाले मरीजों की लू के लक्षणों की जांच करने, उचित प्रबंधन करने के भी निर्देश दिए गए हैं।तेज धूप में ज्यादा देर तक रहना लू लगने का प्रमुख कारण होता है। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिससे इलेक्ट्रोराइड का असंतुलन हो जाता हैं। गर्मी के दौरान लू से बचाव के लिए नियमित पानी पीते रहे। धूप में बाहर निकलते समय शरीर को सूती वस्त्रों से ढांककर रखें। लू से बचाव के लिए दोपहर 12 बजे से 03 बजे के बीच धूप में न निकलें, इस समय लू लगने की संभावना अधिक होती है। मदिरा, चाय, कॉफी इत्यादि का अत्याधिक सेवन न करें। कोई भी अधिक मेहनत का कार्य करते समय पर्याप्त पानी पीते रहें और डिहाइड्रेशन से बचें। बासे भोजन का सेवन न करें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने बचें। इसके साथ ही लू के लक्षण दिखाई देने पर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें।

खंडवा में जमीन की लड़ाई के दौरान हथियार रखने का आरोप

मीडिया ऑडीटर, खंडवा (निप्र)। खंडवा के एक पुलिस थाने में बीएमडब्ल्यू कार जब्त किए जाने का मामला सामने आया है। इतनी महंगी कार को पुलिस अभिरक्षा में लिया जाना शहर में पहली बार माना जा रहा है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार, शहर के दो प्रतिष्ठित कॉलोनाइजरों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद में एक पक्ष पर कार में फरसा जैसे धारदार हथियार लाने और दूसरे पक्ष को धमकाने का आरोप लगा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

पदमनगर थाना पुलिस ने अभिरक्षा में ली कार: मामला पदमनगर थाना क्षेत्र का है, जहां बुधवार को पुलिस ने एक बीएमडब्ल्यू कार को अभिरक्षा में लिया।

नौतपा का तीसरा दिन, अधिकतम पारा 44 डिग्री दर्ज

सागर समेत संभाग के 5 जिलों में लू का अलर्ट, 28 मई के बाद बादल छाने का अनुमान

मीडिया ऑडीटर, सागर (निप्र)। सागर में नौतपा के दौरान झुलसा देने वाली गर्मी का दौर चल रहा है। सुबह 8.30 बजे से ही सूरज की किरणों में तल्खी महसूस हो रही है। सुबह 10.30 बजे से धूप में चुभन से लोग परेशान हैं। इस समय सागर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं रात का पारा 30 डिग्री पर आ गया है। जिस कारण दिन के साथ रात में भी लोग भीषण गर्मी से हलाकान हैं। नौतपा के तीसरे दिन बुधवार को शहर में झुलसाने वाली धूप रही। सुबह से बाजार में लोगों ने अपने जरूरी काम निपटाए और 11.30 बजे के बाद बाजार की सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई।

धूप का असर बढ़ते ही दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटे गर्मी के तेवर ऐसे ही बने रहेंगे। 28 मई के बाद मौसम में बदलाव आने की संभावना है। जिसके असर से आसमान में बादल छाएंगे और हवा-आंधी और बारिश का अनुमान बना हुआ है। इसी के साथ जिले में प्री-मानसून एक्टिविटी की शुरुआत होने की संभावना जताई गई है।

संभाग के 4 जिलों में लू का अलर्ट: मौसम विभाग ने सागर जिले में लू चलने की संभावना जताई है। इसके साथ ही संभाग के दमोह, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी और टीकमगढ़ में लू का अलर्ट जारी किया गया है।

इस दौरान टीकमगढ़ में रात का तापमान बढ़ा हुआ रहेगा। जिससे रात में गर्मी का असर ज्यादा होने का अलर्ट जारी किया है। इस समय सागर संभाग के जिलों में 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दिन का तापमान चल रहा है।

गर्मी में खूब पानी पिएं, खाली पेट घर से न निकले

गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी पिये भले ही आपको प्यास नहीं लगी हो। यात्रा करते समय पीने का पानी साथ रखें। पानी, छाछ, ओआरएस का घोल या घर में बने पेय पदार्थ लस्सी, नीबू पानी, आम का पना आदि का सेवन करें। सूती, ढीले व आरामदायक कपड़े पहनें, धूप में निकलते समय अपना सिर ढंककर रखें, टोपी, कपड़ा, छतरी का उपयोग करें। उच्च जल सामग्री वाले मौसमी फल और सब्जियां खाएं। भरपेट ताजा भोजन करके ही घर से निकलें। धूप में अधिक नहीं निकलें।

सागर संभाग के जिलों का तापमान

जिला	अधिकतम तापमान	न्यूनतम तापमान
सागर	44.0	30.0
दमोह	45.0	26.2
खजराहो (छतरपुर)	46.4	28.4
टीकमगढ़	45.0	29.6
निवाड़ी	44.0	28.0

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की मल्लुपुरा बीट बनी टाइगर हब : बाघिन के साथ आराम फरमाते और शिकार खाते दिखे तीन शावक, पर्यटक हुए रोमांचित

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व,(एसटीआर) के चूरना रेंज की मल्लूपूरा बीट इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहां जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को एक साथ 3 से 4 टाइगर दिख रहे हैं। तीन दिन पहले जंगल सफारी करने गए पर्यटकों को बाघिन को अपने शावकों के साथ घास के मैदान में आराम फरमाते दिखी। हरी घास पर तीन शावकों के साथ बाघिन को देख पर्यटक रोमांचित हो उठे। पर्यटकों ने अपने कैमरे में इस रोमांचक नजारे को कैद किया। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि बाघिन आराम फरमा रही। कुछ कदम दूरी पर अपने तीन शावक भी है। जिसमें दो शावक शिकार किए जानवर को खा रहे। फिर कुछ देर बाद तीनों शावक भी बाघिन के साथ गर्मी से बचने हरी घास पर आराम फरमाने लगे। एसटीआर सूत्रों के मुताबिक बाघिन झल्लाई बाघिन है। जिसके तीन शावक है। जो मल्लूपूरा बीट में ही अक्सर विचरण करती है। इसी बीट में एक ओर बाघिन जिसे स्थानीय फॉरेस्ट कर्मी सुपल्लई बाघिन बोलते है। वो इसी क्षेत्र में विचरण करती है। जंगल सफारी करने आ रहे पर्यटकों को बाघिन शावकों के साथ दिख रही है।मल्लूपुरा बीट में बाघों की चहलकदमी बढ़ गई है। जिस वजह पर्यटक भी जंगल सफारी करने पहुंच रहे।

साइबर तहसील 2.0 से नामांतरण प्रक्रिया हुई डिजिटल, पारदर्शी और सरल,5.60 लाख से अधिक ऑनलाइन नामांतरण प्रकरणों का हुआ त्वरित निराकरण

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन, प्रशासनिक पारदर्शिता और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य नागरिकों को सरकारी सेवाएं सरल, सुगम और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में प्रारंभ की गई 'साइबर तहसील 2.0' पहल राजस्व प्रणाली में ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन का माध्यम बनी है। भूमि नामांतरण प्रक्रिया को डिजिटल और केंद्रीकृत बनाकर इस व्यवस्था ने नागरिक सुविधाओं को अधिक सहज और प्रभावी बनाया है और ईज़ ऑफ़ लिविंग को मजबूत किया है।

डिजिटल व्यवस्था से त्वरित हुआ नामांतरण निराकरण: 'साइबर तहसील 2.0' व्यवस्था से अब तक प्रदेश में 5.60 लाख से अधिक ऑनलाइन नामांतरण प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है। पहले जहां नामांतरण की प्रक्रिया में लगभग 70 दिन का समय लगता था, वहीं अब अधिकांश प्रकरण मात्र 20 से 25 दिनों में पूरे हो रहे हैं। इससे नागरिकों के समय, श्रम और धन की बचत सुनिश्चित हुई है।

'साइबर तहसील 1.0' से '2.0' तक का सफल विस्तार: राज्य सरकार ने साइबर तहसील व्यवस्था की शुरुआत 'साइबर तहसील 1.0' के रूप में की थी। इसके अंतर्गत प्रारंभिक चरण में पूर्ण खसरा से संबंधित नामांतरण प्रकरणों को शामिल किया गया था। रजिस्ट्री के बाद पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होती थी और मैन्युअल हस्तक्षेप को न्यूनतम रखा गया था। इस व्यवस्था की सफलता को देखते हुए सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए 'साइबर तहसील 2.0' लागू की। इसमें अब आंशिक खसरा, अर्थात भूमि के किसी हिस्से की बिक्री से संबंधित नामांतरण प्रकरणों को भी डिजिटल प्रणाली में शामिल किया गया है।

आंशिक खसरा प्रकरणों का समाधान हुआ सरल: आंशिक खसरा से जुड़े मामले तकनीकी रूप से अधिक जटिल माने जाते हैं, क्योंकि इनमें भूमि के हिस्से का सीमांकन, रिकॉर्ड संशोधन और संबंधित जानकारी का सटीक अद्यतन आवश्यक होता है। 'साइबर तहसील 2.0' ने इस चुनौती का समाधान डिजिटल तकनीक से किया है। इससे राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनी है। साथ ही भूमि संबंधी विवादों की संभावनाओं में भी कमी आई है।

प्रदेशभर में प्रभावी रूप से लागू व्यवस्था: 'साइबर तहसील 2.0' वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में प्रभावी रूप से संचालित हो रही है। यह व्यवस्था प्रदेश की लगभग 1,192 क्षेत्रीय तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अदालतों के साथ रीयल-टाइम समन्वय में कार्य कर रही है। केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली से प्रकरणों की निगरानी, प्रगति की समीक्षा और समयबद्ध निराकरण अधिक प्रभावी हुआ है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित स्वचालित दस्तावेज़ खोज और वैधता समाप्ति अलर्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हुआ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नागरिक सेवाओं के लोक-कल्याणकारी एवं डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक युगांतरकारी नवाचार करते हुए एमपी लॉकर ऐप को राज्य स्तरीय डिजिटल दस्तावेज़ प्लेटफ़ॉर्म के रूप में स्थापित किया गया है। यह प्रयास 'डिजिटल गवर्नेंस' एवं 'पेपर लेस एडमिनिस्ट्रेशन' के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार की एक उल्लेखनीय और अभूतपूर्व उपलब्धि बनकर उभरा है। इससे प्रदेश के नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण शासकीय अभिलेखों व प्रमाण-पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल कवच प्राप्त हुआ है। यह ऐप गुगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।

दस्तावेज़ों का सुरक्षित संचयन एवं सर्वसुलभ उपलब्धता: एमपी लॉकर ऐप से राज्य के नागरिक अपने महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज़ों- जैसे विभिन्न प्रमाण-पत्र, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस), अनापत्ति प्रमाण-पत्र कर रसीदें एवं अन्य विधिक प्रलेखों को कभी भी और कहीं से भी सुरक्षित रूप से प्राप्त, संचयित एवं साझा कर सकते हैं। वर्तमान में इस अत्याधुनिक प्लेटफ़ॉर्म पर eNP, ABPAS एवं भोपाल नगर निगम से संबंधित 22 से अधिक नागरिक केंद्रित सेवाएँ सुगमता से उपलब्ध हैं। इनमें मुख्य रूप से संपत्ति कर रसीद, जल कर रसीद, व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लाइसेंस), अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, भवन अनुज्ञा (बिल्डिंग परमिशन) तथा संपत्ति नामांतरण जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाएँ समाहित हैं।

नवाचार के मुख्य आकर्षण: एआई क्षमताएं और 'वैधता समाप्ति चेतावनी' एमपी लॉकर ऐप की विशेषता इसका कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित स्वरूप है, जो नागरिकों को निम्नलिखित विशिष्ट सुविधाएँ प्रदान करता है। स्वचालित दस्तावेज़ अभिज्ञान नागरिकों को अब अपने दस्तावेज़ों को खोजने के लिए किसी मैन्युअल अन्वेषण या जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। यह ऐप पंजीकृत मोबाइल नंबर से संबद्ध समस्त शासकीय दस्तावेज़ों की स्वतः पहचान कर उन्हें तत्काल स्क्रीन पर प्रदर्शित कर देता है।

वैधता समाप्ति पूर्व सूचना: नागरिक हितों को सर्वोपरि रखते हुए इसमें रिमाइंडर सिस्टम जोड़ा गया है। यह प्रणाली किसी भी दस्तावेज़ या लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से पूर्व ही नागरिक को स्वतः सूचित कर सचेत कर देती है, जिससे समय रहते उनका नवीनीकरण सुनिश्चित हो सके और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

नॉर्वे चेस: प्रग्गनानंदा और गुकेश ने आर्मागेडन में दर्ज की जीत

ओस्लो, एजेंसी। नॉर्वे चेस 2026 की शुरुआत ओस्लो में काफी रोमांचक अंदाज में हुई। भारतीय खिलाड़ी आर प्रग्गनानंदा और वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश दोनों ने अपने-अपने पहले क्लासिकल मैच ड्रॉ खेले। इसके बाद हुए आर्मागेडन टाई-ब्रेक में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल करके अपने अभियान की बेहतरीन शुरुआत की। वहीं, दिव्या ने वर्ल्ड चैंपियन वेनजुन को शिकस्त दी। प्रग्गनानंदा ने आक्रामक प्रदर्शन के साथ टाईब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, तो गुकेश ने क्लासिकल मुकाबले में मुश्किल एंडगेम से बचने के बाद विंसेंट कीमर के खिलाफ शानदार वापसी की। हालांकि, शुरुआती राउंड का सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब अलीरेजा फिरौजा ने क्लासिकल चेस में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को चौंका दिया, जिससे नॉर्वे के सुपरस्टार को घरेलू मैदान पर एक दुर्लभ हार का सामना करना पड़ा। प्रग्गनानंदा और वेस्ली सो ने एक संतुलित क्लासिकल गेम खेला जो एक

दिव्या ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया

तनावपूर्ण मुकाबले के बाद ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इसके बाद आर्मागेडन टाई-ब्रेक में प्रग्गनानंदा ने तेज और आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने खेल की गति बढ़ाई और लगातार दबाव बनाते हुए बेहतर चालें खेलीं, जिससे उन्हें बोनस प्वाइंट्स हासिल करने में मदद मिली और उन्होंने निर्णायक गेम अपने नाम कर लिया।

एक और बेहद रोमांचक मुकाबले में गुकेश का सामना जर्मनी के विंसेंट कीमर से हुआ। मैच के एंडगेम में ऐसा लग रहा था कि कीमर जीत के करीब हैं और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन गुकेश मुश्किल में पड़ गए हैं, लेकिन गुकेश ने शानदार धैर्य और मजबूत डिफेंस दिखाते हुए हार टाल दी और मुकाबले को ड्रॉ कराने में सफल रहे। इसके बाद आर्मागेडन टाई-ब्रेक में उन्होंने उसी आत्मविश्वास के साथ खेल जारी रखा और बाजी पलटते हुए शानदार जीत दर्ज की।

कार्लसन पर फिरोजा की जीत दिन का सबसे अहम नतीजा साबित हुई। कार्लसन गेम के ज्यादातर हिस्से में कंट्रोल में दिखे, लेकिन समय की बहुत ज्यादा दिक्कत की वजह से एक बड़ी गलती कर बैठे, जिसका पूरा फायदा फ्रेंच ग्रैंडमास्टर ने उठाया और ओपन सेक्शन में इकलौती क्लासिकल जीत दर्ज की।

महिला टूर्नामेंट में, मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जू वेनजुन और दिव्या देशमुख का मैच भी तनाव से भरे मुकाबले के बाद ड्रॉ पर खत्म हुआ। दिव्या ने आर्मागेडन के निर्णायक गेम में जबरदस्त प्रदर्शन किया और आर्मागेडन टाईब्रेक गेम जीत लिया। वहीं, बिबिसारा अस्सौबायेवा ने क्लासिकल शतरंज में भारत की नंबर 1 खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को मात दी।

एना मुजीचुक और झू जिनर ने अपना क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ किया, जिसके बाद झू आर्मागेडन में जीतकर अतिरिक्त पॉइंट हासिल करने में सफल रहीं। मौजूदा महिला वर्ल्ड चैंपियन जू वेनजुन को भी भारत की दिव्या देशमुख ने ड्रॉ पर रोका, जिन्होंने बाद में आर्मागेडन में उन्होंने जीत हासिल करके सभी को प्रभावित किया।

बुमराह को अब भी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मानते हैं डिविलियर्स

जोहांसबर्ग, एजेंसी। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खराब प्रदर्शन के बाद निशाने पर आये तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का बचाव किया है। डिविलियर्स ने कहा है कि बुमराह अभी भी विश्वकप के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं और महज एक सत्र खराब होने से उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता है। डिविलियर्स ने माना है कि बुमराह मुंबई इंडियंस की ओर से उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाये हैं पर कहा कि इस प्रकार का खराब दौर हर क्रिकेटर के जीवन में आता है पर इसका कतलब ये नहीं कि वे बेकार हो गये। साथ ही कहा कि इससे उनकी गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता और वह जल्द ही अपने पुराने रंग में लौटेंगे।

बुमराह के लिए यह सत्र बेहद खराब रहा है। पूरे टूर्नामेंट में वह 13 मैच केवस 4 विकेट ही ले पाये। ये उनके जैसे खिलाड़ी के लिए बेहद निराशाजनक है। उनका गेंदबाजी औसत 102.50 रहा, जो टी20 क्रिकेट के इतिहास में एक ही

टूर्नामेंट में 40 या उससे अधिक ओवर फेंकने वाले गेंदबाज का अब तक का सबसे खराब औसत माना जा रहा है।

डिविलियर्स ने बुमराह का बचाव करते हुए कहा कि एक खराब प्रदर्शन किसी भी खिलाड़ी की क्लास को खत्म नहीं कर सकता। उन्होंने जोर देकर कहा, यह बुमराह के आईपीएल करियर का सबसे खराब सत्र रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनका औसत 100 से ज्यादा रहा, लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इन सबके बावजूद, मुझे अब भी लगता है कि वह दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। डिविलियर्स ने बुमराह की क्षमताओं पर अटूट विश्वास व्यक्त किया। साथ ही कहा कि वह जल्द ही अपने पुराने शानदार अंदाज में वापसी करेंगे। यह भी याद रखन चाहिये कि आईपीएल से पहले टी20 विश्व कप में उन्होंने भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

बुमराह को तरोताजा होने के लिए प्रबंधन ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए आराम दिया है ताकि वह पूरी तरह से फिट हो सकें। हैइस साल टीम इंडिया का अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहने वाला है और ऐसे में मुख्य गेंदबाजों की फिटनेस प्रबंधन की प्राथमिकता है।

टी20 में दोहरा शतक लगाना चाहते हैं वैभव सूर्यवंशी

गेल का 175 रनों का रिकार्ड तोड़ना भी है लक्ष्य

मुम्बई, एजेंसी। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इस सत्र में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से कई नये रिकार्ड बनाने वाले राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का लक्ष्य अब टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक लगाना है। 15 साल की उम्र में ही इस सत्र में 500 से अधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप के दावेदारों में शामिल वैभव का कहना है कि वह वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल का 175 रनों का रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहते हैं।

वैभव ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन के एक शो में ये बातें कहीं। जब पीटरसन ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अर्धशतक का जश्न मनाना अच्छा लगता है तो वैभव का जवाब था, मुझे 50 रन का जश्न मनाना ज्यादा पसंद नहीं है। मैं टी20 में 200 रन बनाना चाहता हूं। मैं गेल का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूं। उनका ये बयान सोशल मीडिया में छा गया है। गौरतलब है कि गेल ने आईपीएे 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ मात्र 66 गेंदों में नाबाद 175 रन बनाए थे।

एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप पर हैं मनु की नजरें

नई दिल्ली, एजेंसी। ओलंपिक पदक विजेता महिला निशानेबाज मनु आजकल एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियों में लगी हैं। मनु का लक्ष्य इन टूर्नामेंटों में बेहतर प्रदर्शन कर पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन चक्र के लिए अपनी दावेदारी पक्की करना है। मनु का कहना है कि अभी उनका ध्यान अपना फॉर्म बनाये रखते हुए बेहतर प्रदर्शन करने पर है। मनु ने दृढ़ता से कहा, इस साल एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स हमारे सामने हैं, और हम इन दोनों बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कोच के साथ बैठकें की हैं और आगामी टूर्नामेंट्स तथा अपनी तैयारी की एक संपूर्ण और सुनियोजित रूपरेखा तैयार कर ली है। इससे ये साफ है कि उनकी रणनीति केवल तात्कालिक सफलता पर नहीं, बल्कि एक लंबी अवधि की योजना का हिस्सा है।

उन्होंने पिछले साल 10 मीटर एयर पिस्टल में वर्ल्ड कप रजत पदक जीता और इस साल भी 25 मीटर पिस्टल में एशियन चैंपियनशिप में रजत हासिल किया। अब उनका लक्ष्य एक बार फिर अपनी पुरानी, शीर्ष स्तरीय लय हासिल करना है, जो उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक निर्विवाद मजबूत दावेदार बनाएगी। यह वापसी केवल उनके लिए नहीं, बल्कि भारतीय शूटिंग जगत के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होगी।

2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक का क्वालिफिकेशन चक्र भी इसी साल से शुरू हो रहा है, और मनु भाकर इस पर भी अपनी पैनी निगाहें जमाए हुए हैं। उनका मानना है कि एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजनों में किया गया दमदार प्रदर्शन न केवल उन्हें वर्तमान सत्र में सफलता दिलाएगा, बल्कि लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए भी एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करेगा। खेल के साथ अपने व्यक्तिगत जुड़ाव को भी मनु ने साझा किया। उन्होंने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग की वापसी पर अपनी खुशी व्यक्त की। अपने खेल जीवन के अलावा, मनु ने अपने व्यक्तिगत जीवन में आए एक महत्वपूर्ण बदलाव का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया, मैं अब एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं। यह आध्यात्मिक यात्रा ओलंपिक के दौरान ही शुरू हुई थी, और अब मैं पूरी तरह से इस रास्ते पर आगे बढ़ रही हूं। यह नया दृष्टिकोण उन्हें मानसिक शांति और एकाग्रता प्रदान कर रहा है, जो एक उच्च-स्तरीय एथलीट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

त्रिशा जॉली: पिता ने पहचानी प्रतिभा बैडमिंटन की खातिर छोड़ा शहर

कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को दिलाया पदक

नई दिल्ली, एजेंसी। बड़ी पुरानी कहावत है, जहां चाह, वहां राह। बैडमिंटन की दुनिया में सफलता के नए आयाम छूने की ऐसी ही चाहत भारत की स्टार खिलाड़ी त्रिशा जॉली की भी थी। बैडमिंटन के खेल से इस कदर लगाव हुआ कि ट्रेनिंग के लिए अपना शहर छोड़कर हैदराबाद शिफ्ट हो गई। कड़ी मेहनत, लगन और दमदार प्रदर्शन के बूते त्रिशा आज इस खेल में किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। त्रिशा का जन्म 27 मई, 2003 को केरल में हुआ। बचपन से ही त्रिशा को बैडमिंटन में खास रुचि थी। उनके पिता स्कूल में शारीरिक शिक्षक (पीटी टीचर) थे। त्रिशा की प्रतिभा और इस खेल के प्रति उनके लगाव को पिता ने ही पहचाना। पिता की देखरेख में त्रिशा इस खेल की बारीकियां सीखने लगीं। हालांकि, केरल में बैडमिंटन के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। इसी वजह से त्रिशा ने हैदराबाद शिफ्ट होने का फैसला किया और यहां आकर उन्होंने गोपीचंद एकेडमी में दाखिला लिया। इसके बाद त्रिशा इस खेल में रमती गई और उन्होंने धीरे-धीरे नाम कमाना

शुरू कर दिया। जूनियर स्तर पर लगातार अच्छे प्रदर्शन के बूते त्रिशा ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया।

हालांकि, त्रिशा को सबसे बड़ी कामयाबी साल 2022 में हाथ लगी। बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में त्रिशा ने गायत्री गोपीचंद के साथ मिलकर महिला युगल में कांस्य पदक अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में त्रिशा के खेल ने उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर पहचान दिलाई। इसी साल ऑल इंग्लैंड ओपन में भी गायत्री संग मिलकर त्रिशा ने शानदार प्रदर्शन किया।

रैना ने शुभमन और सुदर्शन की जोड़ी को आईपीएल की सबसे अच्छी जोड़ी बताया

नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने गुजरात टाइटंस टीम के कप्तान शुभमन गिल और सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा है कि इनकी जोड़ी आईपीएल इतिहास की सबसे अच्छी सलामी जोड़ी है। रैना ने कहा कि शुभमन और सुदर्शन ने जिस तेजी और निरंतरता के साथ रन बनाए हैं। ऐसा करने में कोई भी दूसरी जोड़ी सफल नहीं रही है। इन दोनों ने साथ मिलकर केवल 46 पारियों में ही तेजी से खेलते हुए 21 बार 50 या उससे अधिक रनों की साझेदारी की है। इससे उनकी आपसी समझ और मैदान पर एक दूसरे के साथ अच्छे तालमेल का पता चलता है।

रैना ने कहा कि इस जोड़ी ने विराट कोहली और क्रिस बेल के अलावा एबी डिविलियर्स और-विराट की जोड़ी को भी पीदे छोड़ दिया है। रैना ने कहा, जहां गेल और कोहली को 21 बार 50 से अधिक रनों की साझेदारी तक पहुंचने में 59 पारियां लगी थीं, वहीं डिविलियर्स और कोहली ने यह उपलब्धि 76 पारियों में हासिल की थी जबकि शुभमन और सुदर्शन ने यह आंकड़ा केलव 46 पारियों में ही हासिल कर लिया।

इन जोड़ी ने आईपीएल के अलावा टी20 क्रिकेट में भी कई बड़े रिकॉर्ड बनाये हैं। इस जोड़ी ने अब तक 10 शतकीय साझेदारियाँ बनायी हैं, और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह सबसे तेज जोड़ी है। इस जोड़ी ने आईपीएल में बिना कोई विकेट खोये 200 रन के लक्ष्य को भी आसानी से हासिल किया है। इन दोनो ने ही पारी शुरु करते हुए आईपीएल में 2000 से अधिक रन बनाये हैं, और उनकी साझेदारी का औसत 67 से अधिक का है, जो उनकी निरंतरता और एक-दूसरे के प्रति समझ को स्पष्ट रूप से दिखाता है। यह औसत उनकी बल्लेबाजी की गहराई और हर हाल में प्रदर्शन करने की क्षमता भी दिखाता है।

रैना के अनुसार, गिल और सुदर्शन की सबसे बड़ी ताकत उनके बीच की अच्छी समझ और फिटनेस है। उन्होंने समझाया, दोनों बल्लेबाज अविश्वसनीय रूप से फिट हैं और उन्हें अच्छी तरह पता है कि कब आक्रामक होना है और किस गेंदबाज को निशाना बनाना है।

खेल में विकास के बावजूद देश में हर एथलीट को मिलने वाले सम्मान में अंतर: हरमिलन बैंस

चंडीगढ़, एजेंसी। एथलीट हरमिलन बैंस का मानना है कि भारतीय खेलों में तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि देश में बढ़ते सपोर्ट के बावजूद, सभी एथलीटों के लिए मौके और इनाम एक जैसे नहीं हैं। बैंस ने कहा कि खेल करियर के मौके तो दे सकते हैं, लेकिन सिस्टम सभी एथलीटों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करता।

एशियन गेम्स में एक स्वर्ण और दो रजत पदक जीतने वाली भारतीय मिडिल-डिस्टेंस रनर हरमिलन बैंस ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, कुछ एथलीट सफल हो जाते हैं, जबकि दूसरे अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उस स्तर की नौकरी नहीं ले पाते। अगर हम आज के पदक विजेताओं की तुलना पिछली पीढ़ियों के एथलीटों से करें, तो अब हर किसी के लिए स्थिति एक जैसी नहीं है। हरमिलन ने कहा, पहले, बड़े इवेंट्स में पदक जीतने वाले एथलीटों को अक्सरल डीएसपी जैसे ऊंचे सरकारी पदों पर सीधी नियुक्ति मिल जाती थी। मौके आज भी हैं, लेकिन पहले के मुकाबले वे काफी कम हो गए हैं।

हरमिलन ने टीम इवेंट्स में पहचान में अंतर की ओर इशारा किया। रोइंग पदक जीतने वालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एथलीट निराश हो सकते हैं जब टीम के साथी, जो उतनी ही मेहनत करते हैं, उन्हें अलग-अलग इनाम राशि मिलती है।

एथलीट ने मॉडर्न स्पोर्ट्स में रिकवरी और न्यूट्रिशन की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया, प्रशिक्षण के बाद रिकवरी सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है क्योंकि इससे यह तय होता है कि आप अपने अगले सेशन में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए ऐसा खाना, जो शरीर को पोषण दे, बहुत जरूरी है। भारतीय खेल के विकास में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) जैसे संस्थानों की भूमिका को हरमिलन ने अहम माना। उन्होंने कहा, भारत निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है क्योंकि अब कई अच्छे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। साई युवा एथलीटों के लिए एक बेहतरीन मंच है, लेकिन बच्चों को अभी भी नहीं पता कि उस स्तर तक कैसे पहुंचा जाए।

यूनिटी कप फुटबॉल में 27 मई को भारत का मुकाबला जमैका से होगा

24 साल बाद इंग्लैंड में अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलेगी भारतीय टीम

लंदन, एजेंसी। भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम आजकल यूनिटी कप 2026 में भाग लेने इंग्लैंड गयी हुई है। भारतीय टीम यहां अपना पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार 27 मई की रात को दूसरे सेमीफाइनल में जमैका से खेलेगी। ये 24 साल बाद पहला अवसर है जब भारतीय टीम इंग्लैंड की धरती पर कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलेगी। इससे पहले आखिरी बार भारतीय फुटबॉल टीम ने साल 2002 में इंग्लैंड में मैच खेला था। ऐसे में इस मैच को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। फीफा रैंकिंग में अभी भारतीय टीम 136वें स्थान पर है, जबकि जमैका 71वें स्थान पर है। वहीं, पहले सेमीफाइनल में नाइजीरिया और जिम्बाब्वे की टीमें टकरायेंगी। नाइजीरिया की टीम फीफा रैंकिंग में 26वें स्थान पर एक मजबूत दावेदार है, जबकि जिम्बाब्वे 130वें नंबर पर मौजूद है। इस टूर्नामेंट का प्रारूप ऐसा है कि सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमें तीसरे स्थान के लिए भी प्ले-ऑफ मैच खेलेंगी, जिससे सभी टीमों को कम से कम दो अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का मौका मिलेगा। सभी मुकाबले लंदन के द वैली स्टेडियम में खेले जाएंगे। ऐसे में भारतीय टीम के लिए यह इंग्लैंड में अपनी क्षमताओं को साबित करने और अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। मुख्य कोच खालिद जमील की ये पहली परीक्षा होगी।

ओजस्वी सरगुजा सपनों को मिलेगी नई उड़ान, 55 मेधावी विद्यार्थी नीट-जेईई की तैयारी हेतु रायपुर रवाना

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। सरगुजा जिले के मेधावी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नई दिशा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा ओजस्वी सरगुजा योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल की गई है। इस अभिनव योजना के तहत शासकीय विद्यालयों के 10वीं बोर्ड परीक्षा-2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित विद्यार्थियों को नीट एवं जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रायपुर भेजा गया है। जिला खनिज संस्थान न्यास के वित्तीय सहयोग से संचालित इस योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को रायपुर स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान एलेन कैरियर इंस्टिट्यूट में निःशुल्क आवासीय कोचिंग प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने विद्यार्थियों एवं उनके पालकों को संबोधित किया और तीन बसों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह ऐतिहासिक क्षण सरगुजा के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है।

-मंत्री राजेश अग्रवाल: मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि ओजस्वी सरगुजा जैसी दूरदर्शी परिकल्पना आज वास्तविक स्वरूप ले रही है। आज जिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नीट एवं जेईई की तैयारी के लिए भेजा जा रहा है, वे आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर एवं राष्ट्र निर्माता बनकर न केवल अपने परिवार और जिले बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। यह यात्रा केवल रायपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके सपनों, संघर्षों और सफलता की यात्रा है। विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को भी मिला अवसर मंत्री अग्रवाल ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के पांच विद्यार्थियों का चयन होना एक बड़े सामाजिक परिवर्तन का संदेश है। सीमित संसाधनों एवं दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों से निकलकर इन बच्चों ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा कभी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। उन्होंने जिला प्रशासन की इस अभिनव पहल की सराहना की।

जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने बढ़ाया उत्साह: कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष निरुपा सिंह ने विद्यार्थियों को मन लगाकर अध्ययन करने तथा सफल होकर सरगुजा जिले का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवनारायण यादव ने भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान कलेक्टर अजीत वसंत ने योजना की चयन प्रक्रिया, कोचिंग व्यवस्था, आवासीय सुविधाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए विद्यार्थियों एवं पालकों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय अग्रवाल, जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश झा, जनप्रतिनिधि, चयनित विद्यार्थी एवं उनके पालक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

’सुशासन तिहार-2026 ,स्वामित्व योजना अंतर्गत अधिकार अभिलेख मिलने से तुकाराम वर्मा के जीवन में आई नई उम्मीद’

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी पहल सुशासन तिहार-2026 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में प्रभावी साबित हो रही है। इसी कड़ी में विकासखंड खैरागढ़ के जालबांधा में आयोजित समाधान शिविर ग्रामवासियों के लिए राहत और विश्वास का केंद्र बना।

स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्राम घुमर्रा निवासी 30 वर्षीय तुकाराम वर्मा को 86.06 वर्गमीटर भूमि का अधिकार अभिलेख प्रदान किया गया, जिससे उनके लंबे समय से चले आ रहे इंतजार का सुखद अंत हुआ। अधिकार अभिलेख प्राप्त करते ही तुकाराम वर्मा के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दी। उन्होंने बताया कि कई वर्षों से वे भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित शिविर में उनकी समस्या को गंभीरता से सुना गया और आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर उन्हें अधिकार अभिलेख प्रदान किया गया। इससे अब उन्हें अपनी भूमि पर वैधानिक स्वामित्व का प्रमाण मिल गया है। तुकाराम वर्मा ने कहा कि अधिकार अभिलेख मिलने से अब उन्हें भविष्य में शासन की विभिन्न योजनाओं, आवास सुविधा, बैंक ऋण एवं अन्य शासकीय लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गांव स्तर पर इस प्रकार के शिविर आयोजित होने से ग्रामीणों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और समय के साथ आर्थिक व्यय की भी बचत होती है।

’अबूझमाड़ का धोबे गांव- जहां कभी बंदूकें गूंजती थीं, वहां अब नलों से बह रही विकास की धारा’

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। विकास की असली परीक्षा तब होती है जब वह समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला मुख्यालय से करीब 94 किलोमीटर दूर, घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसा अबूझमाड़ का धोबे गांव आज इसी बदलते भारत और बदलते छत्तीसगढ़ की एक जीती-जाती मिसाल बन चुका है। जो इलाका कभी सिर्फ नक्सली हलचलों और विकास से दूरी के लिए जाना जाता था, आज वहां जल जीवन मिशन ने उम्मीदों का एक नया सवेरा ला दिया है। अबूझमाड़ के इस सुदूर अंचल में पहली बार घर-घर शुद्ध पेयजल की सुविधा पहुंची है, जिसने ग्रामीणों की जिंदगी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है।

पूर्व में संघर्षों का दौर नदी-नालों के दूषित पानी से जंग: वर्षों तक धोबे गांव के ग्रामीणों के लिए सुबह की शुरुआत पानी के बड़े संघर्ष के साथ होती थी। अत्यंत दुर्गम क्षेत्र होने के कारण यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा तो दूर, पीने का साफ पानी मिलना भी एक बड़ी चुनौती थी। गांव के लोग पीने के पानी के लिए पूरी तरह से स्थानीय नदी, नालों और झरनों पर निर्भर थे। पहाड़ों से बहकर आने वाला यह पानी न सिर्फ दूषित होता था, बल्कि इसके उपयोग से ग्रामीण लगातार जलजनित बीमारियों की चपेट में रहते थे। विशेषकर महिलाओं और बच्चों का एक बड़ा समय सिर्फ पीने का पानी ढोने में ही बीत जाता था।

’जल जीवन मिशन- ऐसे बदली धोबे गांव की तस्वीर’

सुशासन तिहार 2026, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन की परिकल्पना को गांव-गांव मिल रहा जनसमर्थन

शिविरों के माध्यम से त्वरित निराकरण से बढ़ा जनता का भरोसा

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित सुशासन तिहार अब जनविश्वास और जनभागीदारी का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने तथा प्रशासन को आमजन के द्वार तक ले जाने की इस अभिनव पहल के अंतर्गत गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिला के पेंड्रा विकासखंड के ग्राम पंचायत बम्हनी में जिले का आठवां जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में जहां संवेदनशील कार्यशैली अपनाते हुए मौके पर ही विभिन्न मांगों एवं शिकायतों का त्वरित निराकरण किया गया।

जनता के बीच पहुंचे अधिकारी, मंच से ही हुआ समस्याओं का समाधान: शिविर की सबसे विशेष बात यह रही कि कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने स्वयं आवेदकों के नाम पुकारकर उन्हें मंच के समक्ष बुलाया और संबंधित विभागीय अधिकारियों से उनके आवेदनों की वर्तमान स्थिति तथा निराकरण की जानकारी ग्रामीणों के बीच साझा करने को कहा।

समय-सीमा का निर्धारण: कलेक्टर ने सीमांकन, पेंशन एवं राशन कार्ड से संबंधित आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को दो दिनों के भीतर जांच कर निराकरण सुनिश्चित करने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि यदि कोई प्रारंभिक सीमांकन से असंतुष्ट है, तो वह नियमानुसार पुनः सीमांकन हेतु कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

महिला स्वावलंबन- मुरमुर बनेगा बकरी पालन क्लस्टर: शिविर में बकरी पालन हेतु शेड निर्माण के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर ने त्वरित रणनीतिक निर्णय लिया। उन्होंने आजीविका मिशन और जनपद पंचायत के अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम कोडगार में स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित बकरी पालन की तर्ज पर अब ग्राम पंचायत मुरमुर को भी बकरी पालन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाए, ताकि ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार को नया आयाम मिल सके।

पेयजल, वनाधिकार और राजस्व मामलों पर विशेष ध्यान: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को आवश्यकतानुसार नए हैंडपंप खनन एवं खराब हैंडपंपों की त्वरित मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वन अधिकार पत्र, ऋण पुस्तिका से संबंधित आवेदनों पर वन विभाग के अधिकारियों को अधीनस्थ अमले व रिकॉर्ड के साथ शिविर में ही छानबीन कर त्वरित निराकरण करने को कहा गया।

13 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने उठाया शिविर का लाभ: इस शिविर में ग्राम पंचायत कोडगार, घाटबहरा, बम्हनी, जिल्दा, खरड़ी, मुरमुर, घघरा, अमाडांड, जाटादेवरी, बसंतपुर, सोनबचरवार, लाटा एवं जमड़ीखुर्द सहित कुल 13 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैकरा एवं उपाध्यक्ष राजा उपेन्द्र बहादुर सिंह ने ग्रामीणों से शासन की कल्याणकारी योजनाओं को समझकर उनका अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया।

सुशासन तिहार में सीधे मिला लाभ: यह शिविर केवल शिकायतों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह प्रत्यक्ष लाभ वितरण का प्रभावी मंच बना। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई एवं बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक सहायता राशि के चेक, आबादी भूमि अधिकार पत्र, बी-वन खसरा, वोटर आईडी कार्ड, किसान किताब, प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी, दिव्यांगजनों को छड़ी एवं वॉकर, आयुष्मान कार्ड, मितानिन दवा किट तथा लर्निंग लाइसेंस वितरित किए गए। शिविर में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसडीएम पेंड्रारोड, जिला पंचायत सदस्य पूर्णिमा पैकरा, पवन पैकरा, जनपद अध्यक्ष अजीत हेम कुंवर श्याम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य अधोसंरचना को मिली नई मजबूती- नवापारा स्वास्थ्य केन्द्र में आधुनिक ऑपरेशन थियेटर का लोकार्पण

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़, सुलभ और जनोन्मुख बनाने की दिशा में निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अंबिकापुर स्थित नवापारा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नवीन ऑपरेशन थियेटर का लोकार्पण एवं अतिरिक्त वार्ड निर्माण कार्य का भूमिपूजन संपन्न हुआ। इस गरिमामयी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) के सहयोग से विकसित इस महत्वपूर्ण परियोजना को क्षेत्र की स्वास्थ्य अधोसंरचना के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बेहतर उपचार व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता- मंत्री राजेश अग्रवाल मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ जनहित की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नवापारा स्वास्थ्य केन्द्र में आधुनिक ऑपरेशन थियेटर और अतिरिक्त वार्ड की स्थापना से विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। स्थानीय स्तर पर इन सुविधाओं के विस्तार से अब मरीजों को गंभीर परिस्थितियों में बड़े या दूरस्थ अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे उनके समय और आर्थिक संसाधनों की भारी बचत होगी।

महिलाओं, नवजात शिशुओं और गंभीर मरीजों को मिलेगा त्वरित लाभ: नवीन ऑपरेशन थियेटर और अतिरिक्त वार्ड के निर्माण से अस्पताल की क्षमता और चिकित्सकीय स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

नैनो डीएपी के उपयोग से किसानों को कम लागत में मिलेगा बेहतर उत्पादन कृषि मंत्री नेताम

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण आयातित उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार कर रही है। वर्तमान में राज्य में 9.29 लाख मीट्रिक टन विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद का स्टॉक गोदामों और सोसायटियों में उपलब्ध है। जो निर्धारित लक्ष्य का 60 प्रतिशत है। जबकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयास से केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को इस खरीफ सीजन के लिए 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य किया गया है। यह वित्तीय वर्ष की खपत 14.62 लाख मीट्रिक टन से 93 हजार मीट्रिक टन अधिक है। राज्य सरकार किसानों के धान बुआई एवं उत्पादन प्रभावित न हो इस उद्देश्य से तरल नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया का स्टॉक भी समानांतर रूप से भण्डारित करने की रणनीति पर भी कार्य कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को नैनो डीएपी उर्वरक के उपयोग हेतु जागरूक किया जा रहा है। कृषि क्रांति की ओर एक कदम÷ अभियान के अंतर्गत नैनो डीएपी को फॉस्फोरस एवं नाइट्रोजन युक्त उन्नत तरल उर्वरक के रूप में किसानों के बीच प्रचारित किया जा रहा है, जिससे कम लागत में अधिक एवं संतुलित उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

सुशासन तिहार बना संबलः ट्राइसाइकिल मिलने से खोमीन कल्लो के जीवन में लौटी आत्मनिर्भरता की मुस्कान

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। कई बार छोटी-सी सहायता किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आती है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम पंचायत हांडीटोला की रहने वाली 30 वर्षीय दिव्यांग हितग्राही खोमीन कल्लो की जिंदगी में भी ऐसा ही सकारात्मक परिवर्तन आया है। बौनापन (शॉर्ट स्टेचर) से प्रभावित खोमीन को रोजमर्रा के कार्यों और आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। घर से बाहर निकलना, सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना या छोटे-छोटे जरूरी काम करना भी उनके लिए चुनौती बन जाता था।

40 प्रतिशत दिव्यांगता से जूझ रही खोमीन अक्सर दूसरों पर निर्भर रहने को मजबूर थीं। लेकिन सुशासन तिहार 2026 के तहत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर ने उनके जीवन में नई उम्मीद जगा दी। ग्राम पंचायत हांडीटोला में आयोजित शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें ट्राइसाइकिल प्रदान की गई, जिसने उनके जीवन को नई दिशा दे दी।

खोमीन कल्लो भावुक होकर कहती हैं कि ट्राइसाइकिल मिलने के बाद अब उन्हें अपने दैनिक कार्यों के लिए किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता। अब वे आसपास आसानी से आ-जा सकती हैं और आत्मविश्वास के साथ अपने काम खुद करने लगी हैं। उनके चेहरे पर लौट आई मुस्कान इस बात की गवाही देती है कि शासन की योजनाएं जब जरूरतमंदों तक पहुंचती हैं, तो वे केवल सुविधा नहीं बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता भी प्रदान करती हैं।

सुशासन तिहार 2026, शिविरों में त्वरित निराकरण से जरूरतमंदों को मिली बड़ी राहत

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत प्रदेशभर में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर आमजन के लिए राहत और भरोसे का माध्यम बनते जा रहे हैं। शिविरों में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया जा रहा है।जशपुर जिले के जनपद पंचायत पत्थलगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत घरजियाबथान में आयोजित सुशासन शिविर में समाज कल्याण विभाग को पेंशन हेतु प्राप्त 80 आवेदनों का शिविर स्थल पर ही निराकरण किया गया। जांच उपरांत सभी आवेदक पात्र पाए गए, जिससे हितग्राहियों में खुशी का माहौल रहा।शिविर में दिव्यांग हितग्राही श्री मोहित राम कोरवा को सहायक उपकरण के रूप में बैटरी चलित ट्राई सायकिल प्रदान की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक गोमती साय उपस्थित रहीं।इसी प्रकार मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले में भी सुशासन तिहार 2026 के तहत आयोजित जन समस्या निवारण शिविरों में छब्।म्त् सर्वे के वंचित पात्र हितग्राहियों को जनपद पंचायतों के सहयोग से पेंशन स्वीकृति आदेश पत्र वितरित किए जा रहे हैं। प्रशासन की इस पहल से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ शीघ्रता से मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।

बस्तर का मांझीपाल बना छत्तीसगढ़ का नया इको-टूरिज्म हब, देश-विदेश के पर्यटकों को कर रहा आकर्षित

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। प्रकृति की अनुपम छटा, जनजातीय संस्कृति की आत्मीयता और रोमांच से सराबोर बस्तर अंचल का खूबसूरत ग्राम मांझीपाल आज छत्तीसगढ़ के सबसे तेजी से उभरते इको-टूरिज्म केंद्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित यह मनोरम स्थल अपने घने जंगलों, स्वच्छ कांगेर नदी और ग्रामीण परिवेश की सादगी के कारण देश-विदेश के सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा बस्तर में इको-टूरिज्म, ग्रामीण और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई विशेष पहल का ही परिणाम है कि आज मांझीपाल वैश्विक मानचित्र पर चमक रहा है। इस मॉडल से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि स्थानीय समुदायों को रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं।

कांगेर नदी में बैम्बू राफ्टिंग बना रोमांच का नया केंद्रः मांझीपाल की सबसे बड़ी यूएसपी यहाँ बहने वाली निर्मल कांगेर नदी है। नदी की शांत जलधारा में स्थानीय आदिवासियों द्वारा तैयार पारंपरिक बांस की नावों पर होने वाली बैम्बू राफ्टिंग पर्यटकों को बेहद रोमांचित कर रही है। राफ्टिंग के दौरान सैलानी घने जंगलों की हरियाली, नदी के किनारों की प्राकृतिक सुंदरता और दुर्लभ पक्षियों की चहचहाहट के बीच प्रकृति को बेहद करीब से महसूस करते हैं। यह गतिविधि केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बस्तर के जनजातीय समुदायों की पारंपरिक जीवनशैली और प्रकृति के साथ उनके गहरे जुड़ाव को भी जीवंत करती है।

आमचो लाड़ी होमस्टे, विदेशी मेहमानों को भा रही बस्तर की आत्मीयताः मांझीपाल में स्थित आमचो लाड़ी होमस्टे आज बस्तर की पारंपरिक संस्कृति और ग्रामीण जीवनशैली को करीब से समझने का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन गया है। अपनी अनूठी और आत्मीय मेजबानी, बस्तरिया व्यंजनों के स्वाद और पारंपरिक परिवेश के कारण यह होमस्टे विदेशी पर्यटकों के बीच भी तेजी से अपनी पैठ बना रहा है। आधुनिक शहरों की भागदौड़ से दूर यहाँ आने वाले पर्यटक स्थानीय रीति-रिवाजों को जीते हैं, जंगल का आनंद लेते हैं, बर्ड वॉचिंग (पक्षी अवलोकन) करते हैं और बस्तर के पारंपरिक जीवन के साथ आत्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं।

सामुदायिक पर्यटन से स्थानीय युवाओं को मिल रहा रोजगारः राज्य सरकार की कम्युनिटी-बेस्ड टूरिज्म (सामुदायिक सहभागिता आधारित पर्यटन) नीति का सीधा और सकारात्मक असर अब बस्तर के ग्रामीण अंचलों में देखने को मिल रहा है। मांझीपाल के पर्यटन हब बनने से स्थानीय आदिवासी युवाओं को प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड, राफ्टिंग संचालक, होमस्टे प्रबंधन और बस्तरिया हस्तशिल्प (हैंडीक्राफ्ट) की बिक्री के जरिए सीधे तौर पर स्थायी रोजगार मिल रहा है। इससे न केवल पलायन पर रोक लगी है, बल्कि जनजातीय परंपराओं और स्थानीय विरासत के संरक्षण को भी एक नई दिशा मिली है।

कैसे पहुँचें मांझीपालः पर्यटकों के लिए मांझीपाल पहुँचना बेहद सुगम और आसान है। यह खूबसूरत पर्यटन स्थल जिला मुख्यालय जगदलपुर से मात्र 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जगदलपुर से दरभा मार्ग होते हुए बेहतरीन पक्की सड़क द्वारा निजी वाहन या स्थानीय टैक्सी से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा भी जगदलपुर में ही स्थित है, जिससे देश के किसी भी कोने से यहाँ का आगमन सुलभ हो जाता है। प्रकृति संरक्षण, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर पर्यटन मॉडल का बेहतरीन उदाहरण पेश करता मांझीपाल आज सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, बल्कि बदलते बस्तर की एक नई और गौरवशाली पहचान बन चुका है।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक / प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा विप्र एक्सप्रे प्रेस सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय वार्ड 14 हल्दीबाड़ी एमसीबी छत्तीसगढ़ से प्रकाशित,संपादक संदीप द्विवेदी
आर .एन .आई नं . सी टी एच आई एन /25/ए 1478 फोन नं .7974467831,9589645803, mediaauditor1@gmail .com पीआइबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार , सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा